राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 49 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली,शुक्रवार ,20 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन व पाकिस्तान पर साधा निशाना, दुनिया से आतंक के खात्मे के लिए भारत ने दिया फार्मूला

नई दिल्ली । जब पाकिस्तान समर्थक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा कर पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है तब भारत ने वहां के हालात को क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के लिए खतरनाक बताया है। भारत ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने वालों के साथ ही आतंक को शरण देने वाले स्थलों के खतरे के प्रति भी विश्व बिरादरी का ध्यान आकर्षित कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में आतंकवादी घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरे के विषय पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए आठ सूत्री फार्मूला भी पेश किया। इसमें किसी न किसी बहाने आतंकवाद का महिमामंडन बंद करने और आतंकवाद को लेकर दोहरा मानदंड नहीं अपनाने की अपील की गई है। कहने की जरूरत नहीं कि विदेश मंत्री का इशारा सीधे तौर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ था जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र के तौर पर चिह्नित हो चुका है।

चीन को भी लिया आड़े हाथों– जयशंकर ने आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को भी आड़े हाथों लिया। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में जिस तरह का रवैया चीन अपनाता है, उसे जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया। भारत अगस्त के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना है।

भारत की अध्यक्षता में होने वाली दो अहम बैठकों में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री न्यूयार्क गए हुए हैं। आतंकवाद पर गुरुवार को हुई बैठक की अहमियत अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए बढ़ गई है। जयशंकर के भाषण से साफ है कि नई परिस्थितियों में पाकिस्तान को लेकर भारत का रवैया अब पहले से भी सख्त होगा। दोनों देशों में सीज फायर होने के बाद रिश्तों में तनाव खत्म होने की संभावना जताई जा रही थी। अब हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। जयशंकर ने भले ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था।

उन्होंने भारत पर हुए मुंबई, पठानकोट, पुलवामा हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमें किसी भी सूरत में आतंकवाद के राक्षस से कभी समझौता नहीं करना चाहिए सनद रहे कि इन सभी आतंकी वारदातों में पाकिस्तान में पनाह पाए हुए आतंकी संगठनों का ना सिर्फ नाम आया है, बल्कि उसके सुबूत भी मिल चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री के अलावा इस बैठक में दूसरे कई देशों ने भी अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता को सामने रखा। रूस ने कहा कि वह अफगानिस्तान में उन राजनीतिक ताकतों की मदद करेगा जिनका आतंकवाद के साथ कोई लेना देना ना हो। ब्रिटेन ने चेतावनी दी कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान आतंकवाद का सुरक्षित पनाहगाह ना बने। चीन ने भी कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवाद में विभेद नहीं होना चाहिए। साथ ही आतंकवाद के लिए किसी एक देश को जिम्मेदार ठहराने का चीन ने विरोध किया है। चीन के प्रतिनिधि ने संभवत- भारतीय विदेश मंत्री के भाषण में पाकिस्तान पर किए गए परोक्ष हमले का जवाब दिया है।

जयशंकर ने आइएसआइएल (दायेश) का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि अब भी सीरिया व इराक में इस संगठन का कुछ हिस्सा जिंदा है। इसका वित्तीय विभाग पहले से भी ज्यादा सक्रिय है। इसे लगातार फंड मिल रहा है और अब तो बिटक्वाइन के जरिये भुगतान हो रहा है। भारत के निकट पड़ोस में आइएसआइएल-खोरासन (आइएसआइएल-के) अपना पैर पसारने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में जो हालात अब बने हैं उसका क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर असर दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता है। हक्कानी नेटवर्क की गतिविधियों से हमारी चिंता और बढ़ी है। भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मुहम्मद जैसे संगठन अब भी सक्रिय हैं और उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि परिषद विभेद करने वाला या आत्मसंतुष्ट करने वाला कोई फैसला नहीं करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें किसी भी सूरत में आतंक को पनाह देने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस बारे में जो लोग दोहरी बातें करते हैं, उनका भी विरोध करने का साहस होना चाहिए।

एक नज़र...

23 अगस्त को मोदी से मिलेंगे नीतीश-तेजस्वी

पटना, (एजेंसी)। जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार के मुयमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। मुयमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्विटर पर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम से मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। श्री कुमार ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर पीएम से बिहार के प्रतिनिधिमंडल के मिलने का समय तय हो गया है।

पीटी उषा के गुरु ओपी नंबियार का निधन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश का पहला द्रोणाचार्य अवॉर्ड जीतने वाले और दिग्गज पीटी उषा के कोच ओपी नांबियार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। देश के शीर्ष कोचों में शुमार नंबियार ने 89 साल की उम्र में गुरुवार को अंतिम सांस ली। अपने कोच के निधन पर पीटी उषा ने एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि आपकी खाली जगह को कभी भरा नहीं जा सकेगा। बता दें कि ओपी नंबियार की कोचिंग में ही पीटी उषा देश की शीर्ष एथलीट बनीं।

जामनगर में भूकंप के झटके, दहशत में लोग

जामनगर । गुजरात के जामनगर में गुरुवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिटर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद डर की वजह से लोग घर से बाहर आ गए। हालांकि, अभी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। गुरुवार की सुबह-सुबह मेरठ और कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दोनों ही जगह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, कटरा में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया तो वहीं मेरठ में इसकी तीव्रता 2.7 रही. हालांकि, तीव्रता कम होने से कोई नुकसान नहीं हुआ।

कोविड जागरूकता पर तीन दिनी छायाचित्र प्रदर्शनी शुरू

प्रयागराज । डीएम संजय खत्री ने कहा कि कोविड से अभी सतर्क रहने की जरूरत है, योंकि थोड़ी सी असावधानी से फिर खतरा हमारे लिए, आपके लिए और समाज के लिए कोविड बन सकता है। यह बातें डीएम प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हरि श्याम मानव कल्याण शिक्षा एवं शोध संस्थान अंबेडकर बिहार चौफटका एवं श्री गंगा कल्याण सेवा समिति की ओर से कोविड-19 की जागरूकता, टीकाकरण और मदद के लिए प्रेरित करने को लेकर तीन दिवसीय छाया चित्र प्रदर्शनी उार मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के गांधी वीथिका में शुभारंभ अवसर पर कहीं।

महाराष्ट्र में भाजपा के पास विस्तार का सुनहरा मौका, 2024 में अकेले दम पर सरकार बनाएंगे : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई । भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेन्द्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन में होने के कारण उनकी पार्टी पहले अपने राजनीतिक समर्थन के आधार का विस्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन गठबंधन टूटने के मद्देनजर अगले चुनावी के बाद पार्टी अपनी सरकार बनाएगी.

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अब जब शिवसेना ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ दिया है और कांग्रेस तथा राकांपा के साथ मिलकर सरकार बना ली है, भाजपा के पास राज्य में अपने आधार विस्तार का सुनहरा मौका है. पुणे जिले से शिवसेना नेता आशा बुचाके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रकांत पाटिल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुईं. फडणवीस इसी अवसर पर बोल रहे थे.

बीजेपी के पास सुनहरा मौका– फडणवीस ने कहा, ''भाजपा पहले राज्य में विस्तार नहीं कर पायी क्योंकि वह गठबंधन (शिवसेना के साथ) में थी. अब तीन दल सत्ता में हैं और भाजपा के पास राज्य में अपने आधार विस्तार का सुनहरा मौका है.'' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव (2024 में संभावित) के बाद भाजपा अपने बूते पर सरकार बनाएगी.

सत्तारूढ़ तीनों पार्टियों का दम घुट रहा है– उन्होंने कहा, ''सत्तारूढ़ तीनों पार्टियों का दम घुट रहा है. सत्तारूढ़ गठबंधन वाले दल (शिवसेना) की नेता आशा बुचाके का भाजपा में शामिल होना स्वागत योग्य है.'' भाजपा और शिवसेना के बीच पहली बार 1980 की दशक में महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ. 2014 में गठबंधन कुछ समय के लिए टूटा और दोनों पार्टियों ने अपने बूते पर चुनाव लड़ा.

2014 की दूसरी छमाही में शिवसेना फिर से भाजपा से जुड़ी और गठबंधन ने फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनाई. दोनों दलों ने फिर से 2019 में साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीता. लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर शिवसेना ने अपना रास्ता अलग कर लिया और कांग्रेस तथा राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनायी.

संसद के बाद सड़क की रणनीति पर काम करेंगी सोनिया, बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक

नई दिल्ली. संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष का हल्ला बोल जारी है. इसी कड़ी में संसद के बाद सड़क के लिए विपक्ष की साझा रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है. इस वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, शरद पवार सहित अन्य नेता शामिल होंगे. बैठक में पेगासस, किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को सड़क के ज़रिए आम जनता तक कैसे ले जाया इस पर विस्तृत चर्चा होगी.

विपक्ष ने संसद में एकजुटता दिखाई लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सड़क पर भी ये नेता साझा रणनीति के तहत उतरते नज़र आएंगे? क्या जनता तक विपक्ष संयुक्त रूप से एक योजना लेकर जा पायेगा? क्या 2024 तक ये एकता कायम रह पाएगी? इन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है. बैठक में समान विचारधारा के मुख्यमंत्रियों सहित अन्य बड़े नेता शामिल होंगे.

कांग्रेस विपक्ष की एकता को लेकर आशावादी है. इस बैठक के बारे में कांग्रेस महासचिव तारिक़ अनवर ने कहा कि सोनिया गांधी की ये पहल उसी तरह रंग लाएगी जैसा 2004 में यूपीए के गठन का प्रयोग था.

अनवर ने कहा कि अब सोनिया गांधी समान विचारधारा के दलों के साथ 2024 के लिए 2004 वाला प्रयोग दोहराने जा रही है. बैठक में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने की संभावना नहीं है. सूत्रों के मुताबिक ये दल कांग्रेस की बैठक में शामिल होकर उसकी पिछलग्गू नहीं दिखना चाहते. बाक़ी लेफ्ट दलों, सपा, आरजेडी सहित लगभग 15 दलों के शामिल होने की उम्मीद है. सोनिया गांधी ने यह बैठक पेगासस जासूसी विवाद और इसे लेकर संसद के हाल में संपन्न मानसून सत्र में हुये.

ममता सरकार को हाई कोर्ट का झटका, चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक झटके की तरह है।

हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

बीजेपी का ममता पर हमला– हाई कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उच्च न्यालाय के आदेश का स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी सरकार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी।

उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा को फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

एक तरफ बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो टीएमसी ने नाखुशी जाहिर की है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, मैं इस फैसले से नाखुश हूं। यदि राज्य के कानून-व्यवस्था के किसी भी मामले में सीबीआई जांच करने आती है तो फिर यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा।

मुझे भरोसा है कि राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और फिर जरूरत होगी तो उच्चतम न्यायालय में आदेश को चुनौती देगी।

किसी भी आपरेशन के लिए चौबीसों घंटे तैयार रहे वायुसेना : वायुसेना प्रमुख

नई दिल्ली । एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को गांधीनगर में कमांडरों से कहा कि भारतीय वायुसेना (आइएएफ) को अभियान के लिए चौबीसों घंटे तैयार रहना चाहिए। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। दक्षिण-पश्चिम एयर कमान में कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भदौरिया ने उनसे नई पीढ़ी के योद्धाओं की समझ व क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के आधुनिक तरीकों का लाभ उठाने का आह्वान किया।

दो दिवसीय सम्मेलन के आखिरी दिन मिशन व लक्ष्य को अंजाम देने की तैयारियों की समीक्षा की गई। आइएएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, वायु योद्धाओं व सिविल कर्मचारियों से मुखातिब भदौरिया ने सामरिक तैनाती तथा कोविड संकट से निपटने की दिशा में अनुशासित पहल में अहम योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने वायुसेना में शामिल किए गए नए सेंसर व हथियारों को जल्द क्रियाशील करने पर भी बल दिया।

भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए दूर-दूर तक फैली भारतीय नौसेना: एडमिरल करमबीर सिंह

नई दिल्ली । नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा के उद्देश्य से दूर-दूर तक अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है. 'हैदराबाद सेलिंग वीक' के 35वें संस्करण के समापन समारोह से इतर नौसेना प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा, ÷हमारी नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा के उद्देश्य से दूर-दूर तक फैल गई है.

करमबीर सिंह ने कहा कि नौसेना नियमित रूप से महासागरों में काम कर रही है. हम दक्षिण चीन सागर में गए हैं, हम प्रशांत क्षेत्र में गए हैं और जैसा कि आज हम बोलते हैं, हमारे पास यूनाइटेड किंगडम में एक जहाज है. एडमिरल सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय कच्चे तेल वाहकों की सुरक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि देश का अधिकांश तेल और गैस खाड़ी से आता है.

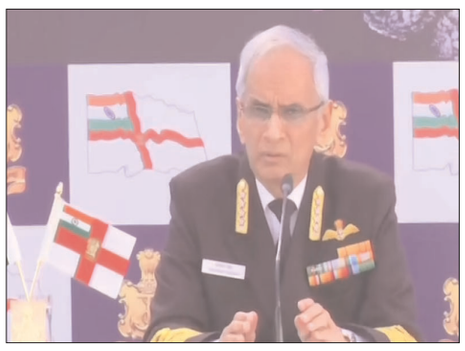

'हर जगह सफलता हासिल कर रही भारतीय नौसेना'– करमबीर सिंह ने आगे कहा कि भारतीय नौसेना के जहाजों को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया है और उन्होंने कहा कि हम अदन की खाड़ी में अपने जहाजों की रक्षा समुद्री डकैती रोधी के हिस्से के रूप में कर रहे हैं और हमारे पास मलक्का जलडमरूमध्य में जहाज हैं. इससे पहले, एडमिरल सिंह ने पुरस्कार विजेताओं को 'हैदराबाद सेलिंग वीक' चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि सफलता उन्हें और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाती है.

उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय रैंकिंग इवेंट कद में वृद्धि जारी है, भागीदारी का विस्तार कर रहा है और उभरते नाविकों के लिए सही लॉन्च पैड प्रदान करने के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा है. हम नाविकों का एक अच्छा आधार चाहते हैं, जिससे हम अच्छे नाविकों का चयन कर सकें और एक बार उन्हें प्राप्त करने के बाद उन्हें विदेशों और देश में अच्छी कोचिंग और अभ्यास दिया जाएगा. ताकि वह एशियाई खेलों और अगले ओलंपिक में पदक जीत सकें.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मोतियाबिंद का आर्मी अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन, हॉस्पिटल से किए गए डिस्चार्ज

नई दिल्ली । राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की गुरुवार की सुबह रेफरल एंड रिसर्च अस्पताल में सर्जरी सफल रही है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की सेना अस्पताल (रेफरल एंड रिसर्च), नई दिल्ली में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। सर्जरी सफल रही और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार 75 साल के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफल रहा है। बता दें कि राम नाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति है उन्होंने अपना कार्यभार 25 जुलाई 2017 को संभाला था। ?

मार्च में हुई थी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का बाइपास सर्जरी– इसी साल 27 मार्च में एम्स के डाक्टरों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का बाइपास सर्जरी किया था। मार्च में राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयाज जारी कर बताया गया था कि राम नाथ कोविंद की तबियत खराब होने से उन्हें एम्स ले जाया गया। जहां डक्टरों की टीम ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें बाइपास सर्जरी करवाने की सलाह दी थी।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 26 मार्च के दिन सीने में दर्द की शिकायत की थी। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको पहले सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद उनको आगे जांच के लिए एम्स रेफर किया गया था। बाइपास सर्जरी होने के बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया था कि बाइपास सर्जरी सफल रही है और उनकी हालत स्थिर है। डक्टरों की टीम द्वारा उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही हैं।

तालिबान ने शुरू की बर्बरता, विदेशी फौजों के मददगारों को मौत के घाट उतार रहे आतंकी

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान ने उन लोगों की तलाशी और हत्या का अभियान छेड़ दिया है जो पूर्व में अमेरिका और नाटो की सेनाओं के लिए काम करते थे, तालिबान को नुकसान पहुंचाते थे। समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों की तलाश राजधानी काबुल सहित सभी शहरों में की जा रही है। यह बात संयुक्त राष्ट्र को प्राप्त हुए गोपनीय दस्तावेज में कही गई है। तालिबान के निशाने पर प्रदर्शन कर रहे आम लोग भी आ गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक पूर्वी प्रांत कुनार की राजधानी असादाबाद में एक रैली के दौरान कई आम लोग मारे गए हैं।

बर्बरता की शुरुआत– रिपोर्ट में कहा है कि दस्तावेज में बताया गया है कि 2001 से 2021 के बीच बड़ी संख्या में अफगान लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाओं का साथ दिया। इन लोगों में अफगानी सेना, पुलिस और खुफिया विभाग के लोग थे। अब इनमें से ज्यादातर लोग गायब हैं। देश के 90 प्रतिशत इलाके में काबिज हो चुके तालिबान लड़ाके अब अपनी सूचनाओं के आधार पर इन गायब लोगों की तलाश कर रहे हैं। इन लोगों के घरों में छापेमारी कर परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है और पकड़ा जा रहा है।

दुश्मनों की तलाश– रिपोर्टों के मुताबिक कुछ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। बीबीसी ने इस तरह के मामलों की पुष्टि की है। पता चला है कि तालिबान के पास ऐसे लोगों की पहले से ही सूचना थी। विदेशी सेनाओं के ये मददगार लोग और उनके परिवार सुरक्षा कारणों से शहरों में ही रहते थे। अब जबकि शहरों पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है तब वे उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अपने दुश्मन रहे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तालिबान की हर संभव कोशिश है कि उन्हें पकड़ा जाए और दंडित किया जाए।

हजारों लोगों ने छोड़ा मुल्क– ऐसे ही छह सौ से ज्यादा लोग अमेरिकी वायुसेना के विमान में बैठकर कतर चले गए हैं। अन्य हजारों लोग जमीनी रास्तों से पड़ोसी देशों में चले गए हैं या छिपे हुए हैं। यह स्थिति तालिबान के प्रवक्ता जमीउल्ला मुजाहिद के यह कहने के बाद है कि हमने सभी को माफ कर दिया है। अब देश में किसी तरह का संघर्ष और युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश पर कब्जा कर चुके तालिबान के पास अब एक समय नुकसान पहुंचा चुके लोगों की तलाश ही सबसे जरूरी काम है। संयुक्त राष्ट्र को नार्वे की संस्था की ओर से मिली रिपोर्ट में मददगार रहे अफगान लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है।

अफगानिस्तान की महिला न्यायाधीशों के लिए चिंता– न्यायाधीशों की वैश्विक संस्था ग्लोबल ज्यूडीशियल इन्टेग्रिटी नेटवर्क (जीजेआइएन) ने अफगानिस्तान की महिला न्यायाधीशों को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि उन्हें अविलंब सुरक्षा मुहैया कराई जाए जिससे वे सुरक्षित तरीके से अपना काम करती रह सकें। उल्लेखनीय है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी कानून लागू करने की घोषणा की है। इस कानून के तहत अपराधों के लिए दोषियों को सार्वजनिक रूप से क्रूर तरीकों से दंडित किया जाएगा।

केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों - रक्षा नवाचार संगठन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए .

संक्षिप्त समाचार

हजारों अफगान शरणार्थियों के अमेरिका के टेक्सास में बसने की संभावना

ह्यूस्टन। अफगानिस्तान में तालिबान से बचने के लिए अमेरिका आने वाले कम से कम 30,000 अफगान शरणार्थियों में से कई को टेक्सास राज्य के विभिन्न शहरों में बसाए जाने की संभावना है। शरणार्थी सेवाओं की एजेंसी ने यह जानकारी दी है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद वहां से हताश होकर अमेरिका भागकर आने वाले कम से कम 30,000 अफगानों को आगामी हफ्तों में अमेरिका में फिर से बसाया जा सकता है। कई अफगान शरणार्थियों को टेक्सास के डलास, फोर्ट वर्थ, ह्यूस्टन और ऑस्टिन शहरों में रखा जाएगा। टेक्सास शरणार्थी सेवा (आरएसटी) के सीईओ रसेल स्मिथ ने एक बयान में कहा, 'अमेरिकी सैना की सहायता करने वाले अफगान नागरिक और उनके परिवार गंभीर खतरे में हैं और अमेरिका में शरण मांग रहे हैं।' स्मिथ ने कहा, 'अब तक, अगले कुछ हफ्तों में 107 परिवारों के ऑस्टिन में स्थानांतरित होने की पुष्टि की गई है। सप्ताहांत में, टी के ऑस्टिन कार्यालय ने सात लोगों के परिवार को फिर से बसाया, और इस सप्ताह चार अतिरिक्त परिवारों का स्वागत करने के लिए कमर कस रहा है। हम जानते हैं कि यह इस लहर की शुरुआत है, और टी इस संकट में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।'

जो बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान सरकार को हथियार बिक्री पर रोक लगायी

वाशिंगटन। अमेरिका ने तालिबान द्वारा देश पर कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान सरकार को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रक्षा ठेकेदारों के लिए बुधवार को जारी किए गए एक नोटिस में विदेश विभाग के राजनीतिक/सैन्य मामलों के ब्यूरो ने कहा कि अफगानिस्तान को लंबित या हस्तांतरण नहीं किए गए हथियारों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में तेजी से बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर रक्षा बिक्री नियंत्रण निदेशालय विश्व शांति को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका की विदेश नीति में उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए सभी लंबित और जारी किए गए निर्यात लाइसेंस और अन्य मंजूरी की समीक्षा कर रहा है। नोटिस में कहा गया है कि वह आने वाले दिनों में रक्षा उपकरण निर्यातकों के लिए अद्यतन जानकारी साझा करेगा।

संभावित काबुल विस्थापितों की तलाश एवं बचाव के लिए तैयार नहीं : ऑस्टिन

वाशिंगटन। अमेरिकी सेना के पास अफगानिस्तान में काबुल हवाईअड्डे को सुरक्षित करने के अपने मौजूदा मिशन को विस्तार देकर राजधानी में मौजूद अमेरिकियों और खतरे का सामना कर रहे अफगानों को एकत्र करने और उन्हें देश से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पर्याप्त बल एवं हथियार नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को यह बात कही। राष्ट्रपति जो बाइडन की 31 अगस्त की समय सीमा से पहले देश छोड़ना चाह रहे लोगों को निकालने और हवाई अड्डे पर लाने संबंधी सवाल उन खबरों के बीच खड़ा हुआ है जिनमें कहा गया कि तालिबान चौकियों ने कुछ निर्धारित निकासियों को रोक दिया है। ऑस्टिन ने कहा, 'मेरे पास काबुल में मौजूदा अभियान को विस्तार देने की क्षमता नहीं है और आप इसे कहां ले जाएंगे? काबुल में आप किस हद तक विस्तार दे सकते हैं और उन बलों को यह करने में सक्षम बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा?' सेना से अवकाश प्राप्त चार सितारा जनरल ऑस्टिन का काबुल में रविवार को तालिबान के कब्जा जमा लेने के बाद से पेंटागन संवाददाता सम्मेलन में दिया गया यह पहला बयान है। उन्होंने अफगानिस्तान में बलों की कमान संभाली थी। उन्होंने कहा कि वह मुख्य रूप से हवाई अड्डे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी निगरानी जरूरी है।

अमेरिकी कांग्रेस पर कैपिटल दंगे से संबंधित फुटेज, अन्य रिकॉर्ड के लिए मुकदमा दायर

वॉशिंगटन। 6 जनवरी को हुए कैपिटल दंगे से संबंधित फुटेज और अन्य रिकॉर्ड के लिए कांग्रेस पर एक अमेरिकी स्वतंत्र पत्रकार ने यह कहते हुए मुकदमा दायर कराया है कि उन अभिलेखों को लोगों की नजर से छुपाना साबित करता है कि विधायी शाखा में पारदर्शिता की कमी है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शॉन मुस्ग्रेव ने कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर मुकदमे में एक जज से कांग्रेस पर एक्सेस के कॉमन लॉ राइट्स को मान्यता देने के लिए कहा, जो कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट (एफओआईए) जैसे सार्वजनिक रिकॉर्ड कानूनों से मुक्त हैं। शिकायत में कहा गया है कि एफओआईए की अनुपयुक्तता का परिणाम, इन कार्यालयों से जनता को और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ संयोजन में, कम पारदर्शिता और उच्च गोपनीयता का कारण बना है।

इराक ने की तुर्की के हवाई हमले की निंदा

बगदाद। इराकी अधिकारियों ने उत्तरी निनवे प्रांत के सिंजर इलाके में तुर्की के एक विमान द्वारा किए गए हवाई हमले की निंदा की है, जिसमें संप्रभुता के उल्लंघन के लिए इसकी अस्वीकृति पर जोर दिया गया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इराकी मंत्रिस्तरीय परिषद ने सिंजर क्षेत्र की स्थिति और वहां सुरक्षा बनाए रखने के उपायों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एक बैठक की। अल-कदीमी के कार्यालय से एक बयान में कहा गया है कि परिषद ने एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है, जो अच्छे पड़ोस के सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती हैं, साथ ही किसी भी पार्टी से स्कोर का निपटान करने के लिए इराकी क्षेत्र के उपयोग को खारिज कर दिया गया है। यह बैठक सिंजर शहर के पास पीकेके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कूल इमारत पर ड्रोन द्वारा किए गए हवाई हमले के एक दिन बाद हुई, जिसमें पीकेके के 18 आतंकवादी मारे गए।

अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अफगानों ने किया प्रदर्शन, लोगों के बीच डर का माहौल

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को छिटपुट स्थानों पर अफगानों ने राष्ट्रध्वज के साथ प्रदर्शन किया तथा शासन संबंधी बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे तालिबान ने हिंसा से उसे दबाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने आयात पर आश्रित 3.8 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश के सामने खाद्यान्न की भारी कमी होने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों ने कहा कि देश के सामने नकदी की भी कमी है तथा तालिबान के सामने वही समस्या है जो नागरिक सरकार के सामने थी , क्योंकि जिस स्तर का अंतराष्ट्रीय सहयोग नागरिक सरकार को प्राप्त था, वैसा सहयोग तालिबान को नहीं मिल रहा है। इन चुनौतियों के आलोक में आतंकवादी किसी भी असंतोष को दबाने के लिए अग्रसर हैं जबकि उसने वादा किया है कि अफगानिस्तान पर अपने पिछले शासन की तुलना में वे उदार होंगे।

कई लोगों को यह डर सता रहा है कि तालिबान महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों के विस्तार के दो दशक के प्रयासों को मटियामेट कर देगा। बृहस्पतिवार को काबुल हवाई अड्डे के समीप कारों में सवार होकर एवं पैदल लोगों ने मार्च निकाला एवं उनके हाथों में अफगान ध्वज के सम्मान में लंबे काले, लाल एवं हरे बैनर थे। यह बैनर अवज्ञा का प्रतीक बनता जा रहा है क्योंकि आतंकवादियों का अपना झंडा है। नांगरहार प्रांत में प्रदर्शन को लेकर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमेंनजर आ रहा है कि एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी है , उसका खून बह रहा है एवं लोग उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खोस्त प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने प्रदर्शन को दबाने के बाद 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। विदेश से स्थिति की निगरानी कर रहे पत्रकारों से यह जानकारी मिली है।

वैसे आतंकवादियों ने प्रदर्शन या कर्फ्यू की बात तत्काल स्वीकार नहीं कीहै। कुनार प्रांत में भी लोग सड़कों पर उतरे। प्रत्यक्षदर्शियों एवं सोशल मीडिया पर डाले गये वीडियो से इसकी पुष्टि हुई। यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब अफगान ब्रिटिश शासन के समापन से संबंधित 1919 की संधि को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस अवकाश मना रहे है। उनका यह प्रदर्शन उल्लेखनीय अवज्ञा है। आतंकवादियों ने बुधवार को हिंसक तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया था। जलालाबाद में प्रदर्शनकारियों ने तालिबान का झंडा हटाकर अफगानिस्तान का तिरंगा लगा दिया। उसी दौरान एक व्यक्ति मारा गया। इस बीच, अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में पहुंचे विपक्षी नेता 'नोदर्न अलायंस' के बैनर तले सशस्त्र विरोध करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यह स्थान 'नोदर्न अलाइंस' लड़ाकों का गढ़ है, जिन्होंने 2001 में तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था। यह एकमात्र प्रांत है जो तालिबान के हाथ नहीं आया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वे तालिबान के लिए कितना गंभीर खतरा पैदा करते हैं क्योंकि महज कुछ ही दिनों में इन आतंकवादियों ने अफगान सशस्त्र बलों के नाममात्र विरोध के बीच करीब पूरे देश पर कब्जा कर लिया है।

तालिबान ने अभी तक उस सरकार के लिए कोई योजना पेश नहीं की है, जिसे चलाने की वह इच्छा रखता है। उसने केवल इतना कहा है कि वह शरिया या इस्लामी कानून के आधार पर सरकार चलाएगा। अफगानिस्तान में विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमुख मेरी एलन मैक्ग्रोर्थी ने कहा, ''हमारी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि खाद्यान्न आयात की मुश्किलों के अलावा सूखे से देश की 40 फीसद फसल नष्ट हो गयी है। उन्होंने कहा,

'' यह वाकई अफगानिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत की घड़ी है और हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस वक्त अफगान लोगों के साथ खड़ा होने की अपील करते हैं। '' तालिबान द्वारा नृशंस शासन लागू करने को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता एवं चिंता के बीच कई अफगान देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह दिवस मध्य एशियाई देश में ब्रितानी शासन का अंत करने वाली 1919 की संधि की याद में मनाया जाता है। तालिबान ने कहा, ''यह सौभाग्य की बात है कि हम ब्रिटेन से आजादी की आज वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जिहादी प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप दुनिया की एक और अहंकारी ताकत अमेरिका असफल हुआ और उसे अफगानिस्तान की पवित्र भूमि से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा।

पाकिस्तान में शिया समुदाय के धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर किया गया विस्फोट,तीन मरे

मुल्तान (पाकिस्तान) (एजेंसी)।

पाकिस्तान में बृहस्पतिवार को शिया मुसलमानों के धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। पूर्वी पंजाब प्रांत के रूढ़िवादी शहर बहावलनगर में यह विस्फोट हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस और एंबुलेंस घटनास्थल की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में घटनास्थल पर घायल अनेक लोग मदद का इंतजार करते दिख रहे हैं।एक शिया नेता खावर शफकत ने एक बयान में बम विस्फोट की पुष्टि की, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी। इस बीच, अधिकारियों ने अशौरा उत्सव से एक दिन पहले देश भर में मोबाइल फोन सेवा को निलंबित कर दिया है।

गनी ने अफगानिस्तान लौटने का संकल्प लिया

दुबई। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने काबुल लौटने का संकल्प लिया है। वह काबुल में तालिबान के प्रवेश करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। गनी ने बुधवार रात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से एक लाइव फेसबुक प्रसारण के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं (संयुक्त अरब) अमीरात में हूं, लेकिन मैं जल्द ही अपने देश लौटूंगा। उन्होंने कहा वह घर लौटने से पहले दूसरों के साथ परामर्श कर रहे हैं। गनी ने कहा कि वह अफगानों के लिए न्याय हासिल करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। गनी ने कहा, मुझे काबुल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, मैं राजधानी

में रक्तपात का कारण नहीं बनना चाहता था। उन्होंने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा, जो लोग सोचते हैं कि मैं भाग गया हूं, उन्हें मुझे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सभी विवरण नहीं जानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि वह खुद को देशद्रोही नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, मैंने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया। हम काबुल के लिए शांति चाहते थे और इसे नष्ट नहीं करना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, इस विफलता के लिए हमारे सशस्त्र बल जिम्मेदार नहीं हैं, राजनेता दोषी हैं। गनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह काबुल की सुरक्षा और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल में बिना किसी लड़ाई के प्रवेश करने और राजधानी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने से कई घंटे पहले गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके थे। उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने खुद को राष्ट्रीय संविधान के अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में तालिबान के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर पश्चिमी देश अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं।

जरुरी होने पर अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी काबुल में रह सकते हैं: बाइडेन

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को लेकर जनता की बढ़ती आलोचना के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वाशिंगटन अमेरिकियों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि जरुरी हुआ तो उसके सैनिक 31 अगस्त की समय सीमा के बाद भी काबुल में रह सकते हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एबीसी न्यूज से बात करते हुए बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया। यह पूछे जाने पर कि क्या जिस तरह से वहां से अमेरिकी सेना को हटाया गया, इससे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। इस पर बाइडेन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सब कैसे हो गया लेकिन हमारा आइडिया बिना किसी अराजकता फैलाये बाहर आने की थी, मुझे

नहीं पता यह सब कैसे हो गया। उन्होंने कहा, जिन चीजों के बारे में हमें नहीं पता था उनमें से एक यह है कि तालिबान लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए क्या करेगा। बाइडेन ने कहा, वे सहयोग कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकलने दे रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों के लिए कुछ और कठिनाई हो रही है, जिन्होंने वहां रहने पर हमारी मदद की। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना जमीन पर मौजूद अमेरिकियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान में अपने मिशन को 31 अगस्त से आगे बढ़ा सकती है। अगर 31 अगस्त के बाद अमेरिकी बचे हैं तो वह क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, अगर अमेरिकी नागरिक बचे हैं, तो हम उन सभी को बाहर निकालने वाले हैं। अफगान सहयोगियों में से अमेरिका खाली करना चाहता है, उन्होंने कहा, प्रतिबद्धता सभी को बाहर निकालने के लिए है। वास्तव में, हम बाहर निकल सकते हैं। यही हम अभी कर रहे हैं। यही वह रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे। साथ ही बुधवार को, राज्य के उप सचिव वेंडी शेरमेन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य उड़ानों ने पिछले 24 घंटों में 2,000 से अधिक लोगों और पिछले कई दिनों में लगभग 5,000 लोगों को वहां से निकाला है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने पहले दिन में एक सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए कहा, अमेरिकी सरकार हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित नहीं कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी भी 15,000 अमेरिकी अफगानिस्तान में हैं।

ब्रिटेन के सांसदों ने अफगानिस्तान को लेकर जॉनसन की आलोचना की

लंदन (एजेंसी)।

ब्रिटेन के सांसदों ने युद्धग्रस्त देश में तालिबान के कब्जे के बीच अफगानिस्तान में स्थिति से निपटने के तरीकों पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आलोचना की। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को संसद के एक आपातकालीन सत्र में बोलते हुए, जॉनसन ने सांसदों से कहा कि अफगानिस्तान की सरकार का पतन अपेक्षा से अधिक तेजी से हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी सरकार इस सिलसिले में तैयार नहीं थी या इसकी कल्पना नहीं की थी। अफगानिस्तान में तेजी से विकसित हो रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए आपातकालीन सत्र बुलाया गया था, जहां हजारों ब्रिटिश नागरिक और स्थानीय सहायक कर्मचारी अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। दूसरी ओर काबुल के हवाई अड्डे पर अराजक निकासी के दृश्यों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारर ने कहा, अफगान बलों के लचीलेपन और तालिबान के बारे में हमारी सरकार की ओर से चौंका देने वाली आत्मसंतुष्टि एक बड़ा गलत अनुमान था। स्टारर ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2020 में अफगानिस्तान में अपनी सेना को वापस लेने का फैसला किया, जिसने ब्रिटेन को 18 महीने का समय दिया कि उसे अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस बहस में आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे सभी ज्ञात समस्याएं थीं, और तैयारी की विफलता रही है। उन्होंने कहा, योजना की कमी माफी के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री पर भारी जिम्मेदारी है। पूर्व प्रधान मंत्री थेरेसा मे ने भी अफगान स्थिति से निपटने के तौर-तरीकों के लिए जानसन की आलोचना की। मे ने पूछा, क्या अफगान सरकार के बारे में हमारी समझ इतनी कमजोर थी? क्या जमीन पर स्थिति के बारे में हमारा ज्ञान इतना अपर्याप्त था?

कौन हैं खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरूल्ला सालेह ? जिन्होंने तालिबान के खिलाफ परचम किया बुलंद

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की वापसी के बाद अमेरिकी समर्थक अशरफ गनी सरकार गिर गई। राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त राष्ट्र अमीरात चले गए। राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया। जिसके बाद उपराष्ट्रपति अमरूल्ला सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें ऐसा करने की शक्ति देता है।

अमरूल्ला सालेह ने दावा किया कि सप्ताहांत में काबुल में तालिबान के प्रवेश करने के साथ राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ कर चले जाने और उनका कोई अता-पता नहीं चलने के बाद उपराष्ट्रपति अब देश के वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके।

कौन हैं अमरूल्ला सालेह ?

राष्ट्रपति अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़कर चले जाने के बाद अमरूल्ला सालेह अकेले ही तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने 34 में से 33 प्रांतों में कब्जा कर लिया है लेकिन पंजशीर को नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में अमरूल्ला सालेह ने उन्हें पंजशीर को जीतने की चुनौती दी है। अमरूल्ला सालेह खुद पंजशीर घाटी से आते हैं और वहीं से तालिबानियों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं।

साल 1972 में जन्में अमरूल्ला सालेह बचपन में ही तालिबानी विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। बचपन में ही अनाथ हो जाने वाले अमरूल्ला सालेह की बहन का तालिबानियों ने अपहरण कर लिया था और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद अमरूल्ला सालेह का तालिबान को लेकर नजरिया बदल गया था और फिर तालिबानी विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए थे।

अमरूल्ला सालेह की किस्मत उस वक्त बदल गई जब उन्होंने अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के बाद सीआईए की मदद की थी। उन्होंने सीआईए के लिए एसेट का काम किया था और फिर अफगानिस्तान में अमेरिकी समर्थक सरकार बनने के बाद उन्हें साल 2004 में वहां की खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था।

राष्ट्रपति हामिद करजई से उनकी कम बनती थी क्योंकि वो तालिबान से बात करने के हिमायती थे। जबकि अमरूल्ला सालेह तालिबान के खिलाफ एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में जुटे थे। लेकिन जून 2010 में आतंकवादी हमले के बाद उन्हें खुफिया एजेंसी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया।

आपको बता दें कि अमरूल्ला सालेह को पाकिस्तान का विरोधी माना जाता है। जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ समर्पित सरकार थी तो उन्होंने अफगान बलों से दूरियां बना ली थी और मुजाहिद्दीन बलों में शामिल हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने साल 1990 में गुरिल्ला कमांडर मसूद के साथ युद्ध लड़ा था।

हेफाजत-ए-इस्लाम प्रमुख जुनैद बाबूनगरी का चटगांव में निधन

ढाका (एजेंसी)।

आतंकवादी संगठन हेफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के प्रमुख जुनैद बाबूनगरी की गुरुवार को चटगांव के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 68 वर्ष का था। उसके अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के बारे में अधिक जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। इस बीच, एक विशेष पुलिस ब्यूरो (पीबीआई) की टीम ने पिछले साल सितंबर में तत्कालीन हेफाजत प्रमुख शाह अहमद शफी की मौत को तेज करने के लिए माहौल बनाने में शामिल होने के संबंध में बाबूनगरी सहित 43 लोगों के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। 1953 में चटगांव के फातिखरी उपजिला के बाबूनगर गांव में जन्मे बाबूनगरी ने पांच साल की उम्र में अल-जमियातुल इस्लामिया अजीजुल उलूम में दाखिला लिया और फिर, अल-जमियातुल अहलिया दारुल उलुम मोइनुल इस्लाम में 10 साल बिताए। 20 साल की उम्र में उसने पाकिस्तान के जामिया उलूम-उल-इस्लामिया में दाखिला लिया और वहां चार साल तक पढ़ाई की। 24 साल की उम्र में, उसने अल-जमियातुल इस्लामिया अजीजुल उलूम, बाबूनगर में पढ़ाना शुरू किया और फिर बाद में वह अल-जमीअतुल अहलिया दारुल उलुम मोइनुल इस्लाम में शामिल हो गया।

संक्षिप्त खबर

जबरन राष्ट्रगान गाने का मामलाः 100 से पूछताछ के बाद 3 पुलिसकर्मियों की पहचान, कराया जाएगा लाई डिटेक्टर टेस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कथित तौर पर पांच घायल लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने वाले तीन पुलिसकर्मियों की पहचान कर ली है. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तीन पुलिस वालों ने घायलों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर किया था, जिसमें से एक घायल की बाद में मौत हो गई थी. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस इस घटना में शामिल होने वाले पुलिसकर्मियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी. बहरहाल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम ने 100 से अधिक पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और दंगों के दौरान बाहर से तैनात पुलिसकर्मियों के ड्यूटी चार्ट सहित कई दस्तावेजों को स्कैन किया. करीब 17 महीनों की जांच पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने तीन पुलिसकर्मियों की पहचान की है. वहीं, इसम मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है और उनकी सहमति के बाद तीनों पुलिस वालों का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा.बता दें कि दिल्ली हिंसा के दौरान यह घटना पिछले साल 25 फरवरी को 66 फुटा रोड हुई थी, जहां दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. इस घटना में कर्दमपुरी निवासी 24 वर्षीय फैजान ने एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. यही नहीं, राष्ट्रगान गाते दिख रहे सड़क किनारे पड़े लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें पुलिसकर्मियों द्वारा इन लोगों को पीटते हुए बार-बार 'आजादी' शब्द बोलते हुए भी सुना गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच टीम ने घटना का वीडियो स्कैन करते पाया कि एक पुलिस वाला आंसू धुएं के हथियार (टीएसएम) ले जा रहा था. इसके बाद रजिस्टर की जांच की. फिर फुटेज के आधार पर पहले डीएपी के साथ तैनात कर्मियों की पहचान की. इसके बाद उनके दो सहयोगियों को एसआईटी ने दरियागंज स्थित उनके कार्यालय में तलब किया था. करीब 17 महीने के कवायद के बाद तीन लोगों की पहचान हुई है.

जलाशयों से 50 मीटर के दायरे में नहीं खुलेंगे पेट्रोल पंप, देशभर में लागू होगा सीपीसीबी का आदेश

नई दिल्ली । नदी, झील, तालाब, वेटलैंड, नहर इत्यादि किसी भी जलाशय के आसपास 50 मीटर तक अब कोई पेट्रोल पंप नहीं खुल सकेगा। जो पेट्रोल पंप पहले से खुले हुए हैं, उन्हें भी समय-समय पर वहां के भूजल और मिट्टी की गुणवत्ता जांच करानी होगी। एनजीटी के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पेट्रोल पंपों को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पूर्व में सीपीसीबी ने पेट्रोल पंपों के लिए सात जनवरी 2020 को गाइडलाइंस जारी की थी। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मद्देनजर इसमें तेल विपणन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि पेट्रोल पंप स्कूलों, अस्पतालों और रिहाइशी इलाके से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। तेल कंपनियों को नए पेट्रोल पंपों पर वैपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) लगाने का निर्देश भी दिया गया था। बाद में एनजीटी ने गाइडलाइंस में जलाशयों को भी शामिल करने का निर्देश दिया।

इसी निर्देश के आलोक में सीपीसीबी ने दो दिन पहले 16 अगस्त को पेट्रोल पंपों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पुराने पेट्रोल पंपों के साथ-साथ जलाशयों से 50 मीटर की दूरी पर खुलने वाले नए पेट्रोल पंपों को भी 100 मीटर तक के दायरे में भूजल और मिट्टी की जांच करनी होगी। मिट्टी की जांच जहां पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक के बगल से ही बोरवेल के जरिये की जानी है, वहीं भूजल की जांच 120 डिग्री पर यानी तीन दिशाओं में करनी है। शुरुआती छह माह में यह जांच बार- बार और बाद में साल भर में एक बार करनी है। जांच के नमूने तेज विपणन कंपनियों की टीम द्वारा लिए जाएंगे तथा इनकी जांच भी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में ही होगी। सीपीसीबी के पूर्व अपर निदेशक डॉ. एस के त्यागी ने पेट्रोल पंपों के लिए संशोधित गाइडलाइंस में भूजल और मिटटी की जांच के लिए तय मानकों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मानक तय करते हुए विशेषज्ञों से राय नहीं ली गई। जो रसायन भूजल के लिए थोड़ी मात्रा में भी हानिकारक हो सकते हैं, वो मिटटी के लिए भी फायदेमंद नहीं हैं। लेकिन दोनों के ही मानकों में काफी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए तय मानकों पर एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

दिल्ली में हुए दंगों पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जताया दुख, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। दिल्ली जैसे शहर में दंगों की बात को लेकर पुलिस कमिश्नर ने दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे शहर में दंगे हुए, मुझे दुख हुआ. पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना नार्थ ईस्ट दिल्ली जिले के कार्यक्रम उम्मीद में पुलिस और स्थानीय लोगों को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे. उनका कहना था कि कोई समाज खराब नहीं होता. समाज में ऐसे लोगों को पहचानें. उन्हें कानून के सामने लाकर सजा दिलवाएं. ऐसा प्रयास ही आप को एकता के सूत्र में लाएगा. उम्मीद के साथ-साथ समाज में एक दूसरे का विश्वास भी हम लोगों को जीतना चाहिए. विश्वास आप तभी जीत सकते हैं जब आप एक साथ मिलकर काम करें. पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिक जवाबदेही होती है कि इलाके में शांति बनाए रखें. आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली से समाज ऐसा होना चाहिए कि जहां पुलिस की जरूरत ही ना हो. पुलिस की जरूरत तब हो जब किसी के पास कोई उपाय ही ना हो.

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली को ऐसा बनाएं कि यहां पर टूरिस्ट बाहर से आए. यहां पर मिलकर लोग अच्छा महसूस करें. यह बड़ा कठिन काम नहीं है. यह सब हो सकता है. आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं. हम लोग मिलकर यह करेंगे. राकेश अस्थाना ने कहा,"मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का लीडर होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में जिससे हमारे देश की एकता अखंडता बढ़ती है, ऐसे कार्यक्रमों में हम आपका साथ देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे और जो सामाजिक सौहार्द है उस में पुलिस की भूमिका है लिए पूरा सहयोग करेंगे.दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपने ऑफिस में बड़ा बदलाव किया है. राकेश अस्थाना ने पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर सचिवालय बनाया है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बने इस कमिश्नर सचिवालय में दो डीसीपी एक एडीशनल सीपी स्तर के अधिकारी और एक एसीपी स्तर का अधिकारी की तैनाती की गई है. आईपीएस अधिकारी रोमिल बनिया को कमिश्नर का ओएसडी और एडिशनल सीपी सचिवालय बनाया गया है. वहीं केपीएस मल्होत्रा को डीसीपी 1 को कमिश्नर सचिवालय में स्थान दिया गया है.

गणतंत्र दिवस पर केजरीवाल सरकार देगी 'दिल्ली वीरता पुरस्कार', मांगे आवेदन

नई दिल्ली । जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर दूसरों की जिंदगी बचाकर बहादुरी का परिचय दिया है। ऐसे बहादुरों को दिल्ली सरकार दिल्ली वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेगी। सरकार सम्मान स्वरूप पुरस्कार पाने वाले को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और दो लाख रुपये देगी। यह पुरस्कार आने वाले गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा। चयनित 10 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें उम्र का बंधन नहीं रखा गया है। यह पुरस्कार निस्वार्थ सेवा के लिए भी दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सभी क्षेत्रों के व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने उन लोगों को पहचानने और सम्मानित करने के वास्ते दिल्ली वीरता पुरस्कारों का गठन किया है जिन्होंने गंभीर खतरे का सामना करने के लिए अनुकरणीय साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया है। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उत्कृष्ट वीरता और निस्वार्थ सेवा के कार्य किए हैं।

पुरस्कार समिति द्वारा केवल एक सितंबर 2019 और 31 अगस्त, 2021 के बीच की अवधि में किए गए वीरता के कार्यों पर विचार किया जाएगा। चयनित बहादुरों को गणतंत्र दिवस 2022 के सरकारी समारोह में सम्मानित किया जाएगा। योग्य आवेदक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी आवेदक की ओर से आवेदन सिफारिशें अपने संबंधित उपायुक्त (राजस्व) को भेज सकते हैं। ये आवेदन 15 सितंबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले वीरता पुरस्कारों का गठन किया था। पिछले परिपत्र के अनुसार पुरस्कार एक ही श्रेणी में दिए जाते हैं और पुरस्कार पाने वाले को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और दो लाख रुपये दिए जाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार भी गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार देती है।

गोला-बारूद, ड्रोन, बतरबंद वाहन बने एसपो के आकर्षण केंद्र, 15 देशों ने प्रदर्शित की मॉर्डन तकनीक

नई दिल्ली। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिये भारत के साथ-साथ दुनिया के तमाम देश इस पर पूरा फोकस बनाये हुये हैं. साथ ही आपदा प्रबंधन के ढांचे को और किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर लेटेस्ट तकनीक पर बल दे रहे हैं. इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण और हथियारों को प्रदर्शित करने के लिये नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में दो दिवसीय इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो-2021 का आयोजन किया गया है. इसमें भारत समेत दुनिया के 15 देश अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस बीच देखा जाए तो सरकारों के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है. आजकल अपराधियों और आतंकवादियों की नई नस्ल अधिक तकनीक की समझ रखने वाली है और इसलिए भारत की पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है. इसके चलते देश के पुलिस बल में राज्यों और केंद्र दोनों में भारी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है. जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते ग्राफ को भी आगे बढ़ाया है, जिसमें अग्रिम बचाव प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की आवश्यकता की मांग बढ़ गई है.

पुलिस के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार को नई और लेटेस्ट टैक्नॉलोजी से अवगत कराने के लिये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2021 काफी अच्छा माना जा रहा है.

एक्सपो में प्रतिभागी बने 15 देशों की कंपनियों ने अपनी लेटेस्ट टैक्नॉलोजी से अवगत कराने के लिये इन सभी को एक छत के नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है. इसमें खासकर उन्नत आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ी 15 से अधिक देशों की टैक्नॉलोजी को प्रदर्शित किया जा रहा है. एक्सपो में लेटेस्ट टैक्नॉलोजी और उपकरण, बचाव अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिये आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं.

इसके अलावा एक्सपो में अडानी ग्रुप ने भी लेटेस्ट टैक्नॉलोजी को प्रदर्शित किया है. भारत और इज़राइल वेपन इंडस्ट्रीज , इज़राइल के संयुक्त उद्यम पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएलआर) ने अपने आईडब्ल्यूआई हथियारों का प्रदर्शन किया है. इसमें टैवोर असॉल्ट राइफल, डीएन स्नाइपर राइफल्स जिसकी रेंज 1200 मीटर से अधिक है, का भी प्रदर्शन किया है. साथ ही मसाडा एबिडेक्सट्रस पिस्टल (दोनों हाथों से इस्तेमाल किया जा सकता है), गैलिल स्नाइपर राइफल और भी कई अन्य लेटेस्ट टैक्नॉलोजी से लैस हथियारों को प्रदर्शित किया है. बताया जाता है कि इनमें से कुछ हथियार पहले से ही भारतीय सशस्त्र बलों, स ी ए पी ए फ (सीआरपीएफ/बीएसएफ/एसएसबी/एसएफएफ) और राज्य पुलिस बलों के पास सेवा में हैं.

वहीं, टाटा संस की एयरोस्पेस और रक्षा शाखा वाली कंपनी टाटा ए एंड डी की नवीनतम पेशकश में मानवयुक्त आईएसआर विमान भी है. यह वाणिज्यिक और सैन्य दोनों का समर्थन करने के लिए सूचना के समन्वित और एकीकृत अधिग्रहण प्रदान करता है. विश्वसनीय पोस्ट मिशन विश्लेषण और डीब्रीफिंग के लिए पूर्ण डिजिटल रिकॉर्डिंग सहित दिन और रात के संचालन के लिए एक उन्नत सामरिक अवलोकन प्रणाली बताई जाती है.

जानकार बताते हैं कि ऐवेटार का ऋ्हहढ्ढ प्लेटफॉर्म एक पिस्तौल को काबाइन और अन्य/च-सीरीज,ऋ्र5, स्न्न, स्न्नक्त और स्नाइपर राइफल्स में विशेष ऑपरेशन के लिए उपयुक्त हथियार में बदल सकता है. यह क्वार्टर कॉम्बैट और पुलिसिंग ऑपरेशन के लिए एक उपयुक्त तकनीक मानी जाती है.

हवा में 10 घंटे तक स्थिर रह सकता आधुनिक ड्रोन- आपदा बचाव एवं राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से भारत की इंडो विंग्स कंपनी ने एक आधुनिक ड्रोन भी लांच किया है जो हवा में 10 घंटे तक स्थिर रह सकता है और स्ट्रीट लाइट की तरह एक बड़े दायरे में रौशनी दे सकता है. आजकल आंतरिक सुरक्षा और आपदा से निपटने में ड्रोन टैक्नॉलोजी बेहद कारगर मानी जाती है. इसको और अपग्रेड करने पर कंपनियां पूरा फोकस बना रही हैं.

प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण केन्द्रों पर एक्सपो के आयोजनकर्ता मुकेश खारिया कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले जिम्मेदारी होने और नये तरह के बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस की भूमिका भी बदल गई है. आज हमें कानून प्रवर्तन एवं भीतरी सुरक्षा को नया आयाम देने के लिए आधुनिक तकनीकों एवं नए इनोवेशन्स की ज़रूरत है.

दो दिवसीय एक्सपो में ये सभी करेंगे शिरकत- इस बीच देखा जाए तो इस एक्सपो में खासकर जो सुरक्षा एजेंसियां केंद्र और राज्य सरकारों के अधीनस्थ सुरक्षा व आपदा प्रबंधन में कार्यरत हैं. उन सभी के शीर्ष अधिकारी इसका अवलोकन करने पहुंचेंगे. इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, आरपीएफ, आरएएफ, जीआरपी, एसटीएफ, एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड पुलिस, एनआईए, वायु सेना, सभी प्रमुख राज्यों के पुलिस विभागों, आयुध निर्माणी बोर्ड, एनसीआरबी, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड विभाग, डीआरडीओ, बीपीआरएंडडी, स्टेट फोरेंसिक लैब्स, एनटीआरओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वायु सेना, नौसेना, सेना आदि प्रमुख रूप से शामिल होंगी.

नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर अफगान लोग।

ई-आटो परमिट में महिलाओं के लिए होगा 35 फीसद आरक्षण

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आने वाले ई-आटो के परमिट के मामले में महिलाओं के लिए 35 फीसद का आरक्षण होगा। परिवहन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ई-आटो परमिट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक है। उसमें इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलने पर परमिट के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली में यह पहला मौका है जब आटो के परमिट महिलाओं को देने की तैयारी है।

दिल्ली सरकार ने ई-वाहन नीति के तहत वाहन पंजीकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए दिल्ली में 4261 ई-आटो परमिट जारी करने का फैसला किया है। दिल्ली की सड़कों पर अभी अधिकतम एक लाख आटो परमिट जारी किए जा सकते है। इसमें 95 हजार आटो परमिट पहले से ही जारी किए जा चुके है। ये ह सभी आटो सीएनजी पर ही चलते हैं। अब सरकार ने बचे हुए 4261 परमिट ई-आटो के लिए आरक्षित कर दिए हैं।

परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार परमिट मिलने के बाद ई-आटो खरीदते समय सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में अभी 2 से 2.27 लाख तक के ई-आटो बाजार में उपलब्ध हैं। सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने के बाद यह आटो 1.5 से 2 लाख रुपये में मिल जाएंगे। ई-वाहनों के पंजीकरण शुल्क पहले से माफ है।

डीटीसी बसों महिला चालक भर्ती की तैयारी- दिल्ली सरकार डीटीसी बसों में भी महिला चालकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। सरकार ने इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिया है। महिला चालकों के लिए काम करने वाली एक संस्था के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत खुद बैठक कर चुके हैं। जिसमें डीटीसी में महिला चालकों की भर्ती की प्रक्रिया के साथ महिला चालकों की उपलब्धता पर बात हुई है।

ऑनलाइन ई-वेस्ट निपटारे में दिलचस्पी दिखा रही जनता, इतने लोगों ने किया पोर्टल पर रजिस्टर्ड

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ई-वेस्ट निस्तारण की ऑनलाइन सेवा को नागरिकों का समर्थन मिल रहा है। अभी तक 1312 नागरिकों ने अपना पंजीकरण किया है तथा ई-वेस्ट निस्तारण संबंधी लगभग 400 अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

दक्षिणी निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र से 25 मीट्रिक टन ई-वेस्ट का अपनी रिसाइकल वर्कशॉप पर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया है। नागरिक घर बैठे ही अपने ई-वेस्ट को बेच सकते है। इसके लिए दक्षिणी निगम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने https://ewaste.mcdservices.online नाम के ऑनलाइन पोर्टल की सेवा आरंभ की है तथा एक टोल फ्री नम्बर 1800-123-005566 भी आरंभ किया है जिसके माध्यम से नागरिक ई-वेस्ट उठवाने संबंधी आवेदन कर सकते हैं।

दक्षिणी निगम ने भारत सरकार के पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सन् 2016 में अधिसूचित नियमों के आधार पर खुली निविदा के द्वारा आर. बी. एच ई-वेस्ट रिसाइकिल हब प्राइवेट लिमिटेड को अपने अधिकार क्षेत्र में ई-वेस्ट उठाने एवं वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण करने के लिए चुना है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 11 जून 2021 से ई-वेस्ट निस्तारण के लिए ऑनलाइन सेवा आरंभ की थी। मुख्यत:- ई-वेस्ट पुराने खराब पड़े या इस्तेमाल में न आने वाले बिजली उपकरणों जैसे टी वी, ए.सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखे, वाशिंग मशीन, लैपटॉप, फ्रिज, इनवर्टर, बैटरी इत्यादि है। यह सभी उपकरण वर्तमान समय में मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही इनके इस्तेमाल के उपरांत खराब होने की स्थिति में कुशल प्रबंधन के अभाव में यह पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारक है। बिजली उपकरणों में आर्सेनिक, कैडमियम, लिथियम, क्लोरीन, ब्रोमिन इत्यादि का अधिक इस्तेमाल होता है तथा इनके कुशल निस्तारण के अभाव में ये अल्सर, कैंसर,अस्थमा इत्यादि बीमारियों का बड़ा कारण है।

1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में जांच करेगी सीबीआई , भ्रष्टाचार के हैं आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस खरीदी मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में सबसे पहले बीजेपी के विधायक विजेंदर गुप्ता ने एलजी से शिकायत की थी. एलजी हाउस ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया था. अब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच करेगी. इस मामले में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जानकारी दी है.

बीजेपी विधायक विजेंदर गुप्ता ने मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद बयान दिया है. उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करने के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

केजरीवाल सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले को दबाने और रफादफा करने का भरसक प्रयास किया. बस खरीद घोटाले में आम आदमी पार्टी ने चुप्पी क्यों साध ली?

जुलाई में की गई थी शिकायत- बता दें कि बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस साल जुलाई में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर बस खरीद मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

उनका कहना था कि बैजल ने जिस तीन सदस्यीय कमेटी से मामले की जांच कराई, उसने खरीद में तमाम खामियां पाई हैं और बसों के सालाना रखरखाव की एएमसी का टेंडर रद्द करने की सिफारिश की है. साथ ही टेंडर को देखने से अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के सबूत भी कमेटी को मिले हैं. बता दें कि बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी रखरखाव के टेंडर और बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. दिल्ली कांग्रेस ने कहा था कि 3413 करोड़ रुपये के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी से कराई जाए. इसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं.

डीडीए की अलग से प्लाट आरक्षित करने की पहल है स्वागतयोग्य

नई दिल्ली । दिल्ली में सस्ते आवास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलग से प्लाट आरक्षित करने की पहल स्वागतयोग्य है। इससे सभी के लिए आवास का सपना सही मायने में मूर्त रूप ले पाएगा। अभी तक डीडीए ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए जिन प्लाटों की नीलामी करता रहा है, उनमें आमतौर पर फ्लैट भी एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी ही बनाए जाते रहे हैं। इन फ्लैटों की कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची होती हैं, लिहाजा यह हर वर्ग की पहुंच में नहीं आ पाते। पहली बार डीडीए ने छोटी आवासीय इकाइयों के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के प्लाट काटे हैं, वह भी फ्रीहोल्ड। इनकी नीलामी भी अगले माह ही संपन्न हो जाएगी।

नीलामी की शर्तें ही यह रखी गई है कि इन प्लाटों में 60 वर्गमीटर के छोटे आवास बनाए जाएंगे, ताकि कम आय वाले लोग भी आसानी से बैंक लोन की सहायता से इन्हें खरीद सकें। दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, इसीलिए यहां अपना घर होने का सपना भी हर कोई देखता है, लेकिन ज्यादातर का यह सपना पूरा नहीं हो पाता। एक बड़ा तबका आज भी किराये के मकान में ही गुजर बसर कर रहा है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना तैयार की है। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने सस्ते आवास की योजना पर काम शुरू किया है। डीडीए की ओर से दिशा निर्देश जारी होने पर फ्लैट बनाने वाले बिल्डर भी मनमानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें तय शर्तों के अनुरूप ही फ्लैट बनाने होंगे और उनकी कीमतें भी उसी हिसाब से रखनी होंगी।

सच बात तो यह है कि एक सरकारी उपक्रम का इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उस पर एक आम आदमी भरोसा कर सकता है। अन्यथा एक छत खरीदने के फेर में न जाने कितने ही लोग जीवन भर की पूंजी गंवा बैठते हैं। डीडीए को चाहिए कि जो पहल उसने की है, उसका क्रियान्वयन भी अपनी ही देखरेख में सुनिश्चित कराए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, कालकाजी मंदिर में पूजा के लिए नीलामी चिंता का विषय

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर के चर्चित धार्मिक स्थलों में शुमार कालकाजी मंदिर परिसर की सफाई व रखरखाव की व्यवस्था से लेकर पूजा की बारी की नीलामी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त किए गए स्थानीय आयुक्त द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट का हवाला दिया है।

बताया जा रहा है कि पुजारियों द्वारा पूजा की बारी की नीलामी की जा रही है और शिकायत यह भी है कि दान का उचित वितरण और वसूली नहीं हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के गर्भगृह व भवन के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने साथ ही लोकल कमिश्नर मनमीत अरोड़ा को 19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच किसी एक दिन कालकाजी मंदिर का दौरा कर दान के संग्रह और सीसीटीवी कैमरों के संचालन की स्थिति देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि निरीक्षण के अगले दिन लोकल कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।

आवेदनकर्ता नीता भारद्वाज की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता नीरज भारद्वाज ने अदालत को बताया था कि मंदिर परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे हैं, ऐसे में दान और संग्रह की मात्रा का पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है।

दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम में की बढ़ोतरी, जानिए क्या है कारण

नई दिल्ली । अफगानिस्तान में इन दिनों तालिबान के कब्जे के बाद से भारत में रहने वाले या घूमने या फिर व्यापार के लिए आए अफगानिस्तान के मूल निवासी परेशान हैं। वह इन दिनों नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अफगानिस्तान दूतावास के चक्कर काट रहे हैं, ताकि उनका वीजा कुछ और दिनों के लिए बढ़ जाए, जिससे वह अधिक समय तक भारत में रह सकें। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर दूतावास के बाहर पुलिस और अर्ध सैनिक बल को बढ़ा दिया गया है। इससे दूतावास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

दिल्ली पुलिस ने अफगानिस्तान दूतावास के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, जिसके बाद से वहां लगातार पीसीआर वैन को तैनात किया गया है। जो उधर आने वाले हर व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं, दूतावास के बाहर भीड़ की स्थिति ना बने, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं, सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि पिछले तीन-चार दिन से लगातार अफगानी लोगों की संख्या दूतावास में बढ़ गई है।

अधिकतर लोग अपने वीजा को बढ़ाने की गुहार लगाने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग पासपोर्ट पर मोहर लगवाने संबंधी काम के लिए भी पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकतर वह लोग हैं, जो पिछले दिनों भारत में रहने के लिए और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दिल्ली व देश के अन्य राज्यों में घूमने के लिए आए हैं। सुरक्षाकर्मियों का कहना है कि अफगानिस्तान के रहने वाले लोगों के चेहरे पर खौफ देखा जा रहा है, जिसके चलते वह दूतावास में आकर अपना काम करा रहे हैं।

उधर तालिबान का पक्ष लेकर मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (एमपीएलबी) के पूर्व प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी घिर गए हैं। बयान में उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तालिबान ने वहां पर मजबूत सेना को धूल चटाई है। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा है। इनमें किसी भी तरह का घमंड नहीं था, बड़े बोल भी नहीं थे। जारी वीडियो बयान में उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज है और हिंदुस्तान का मुसलमान उसे सलाम करता है। हालांकि, इस बयान पर विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आज का तालिबान, पहले के तालिबान के मुकाबले अलग है। तालिबान के आने से अफगानिस्तान की 90 फीसद जनता खुश है।

संपादकीय

किस तरह खोले जाएं स्कूल

अब लगभग 17 महीने हो गए हैं और देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल बंद हैं। लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने से बच्चों को हो रहे मनोवैज्ञानिक, विकास संबंधी और शैक्षणिक नुकसान को अब हर घर महसूस कर रहा है। शोध-अनुसंधान तो इसके दीर्घकालिक असर पड़ने की मुनादी कर रहे हैं। फिर भी, स्कूलों को खोलने की नीतिगत कोशिश की कमी दिख रही है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए विमर्श का मसला 'किस तरह स्कूलों को खोला जाए' होना चाहिए, न कि 'कब'। जब (कोरोना की दूसरी घातक लहर के बाद) हमारे नीति-निर्धारकों और कारोबारियों ने मॉल, सिम व फैक्टरियों को खोलने के तरीके खोज निकाले हैं, तब यह अक्षम्य है कि स्कूलों और बच्चों की अनदेखी की जाए। स्कूलों को खोलना कोई मामूली बात नहीं है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनमें यह भरोसा पैदा किया जाना चाहिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ऐसा करने के लिए, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को आपस में संवाद करना होगा। महामारी को लेकर अनिश्चितताएं कम नहीं हो रहीं, इसलिए स्कूलों को त्वरित और समय के अनुकूल खुद फैसले लेने के योग्य बनाना होगा। इसके लिए अभिनव नीतियों की दरकार होगी, जो स्थानीय स्तर पर फैसले लेने, जमीनी हकीकत को समझने और शिक्षा व्यवस्था को आकार देने वाली मौजूदा केंद्रीकृत सोच (हर जगह के लिए समान नीतियां) को बदल सकने में सक्षम हो। फिलहाल कम से कम तीन नीतिगत कदम उठाए जाने की जरूरत है।

पहला, हमें अभिभावक-शिक्षकों के जुड़ाव का लाभ उठाना होगा और स्कूल खोलने की प्रक्रिया में माता-पिता को शामिल करना होगा। शिक्षा के अधिकार के तहत अभिभावकों के नेतृत्व वाली स्कूल कमेटियों के गठन के बावजूद स्कूली व्यवस्था में अभिभावकों को शामिल करने और स्कूलों को उनके प्रति जवाबदेह बनाने में भारतीय शिक्षा नीति सफल नहीं हो सकी है। हालांकि, लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने और दूरस्थ शिक्षा पर जोर देने का एक अप्रत्याशित सुखद पहलू यह है कि स्कूल, शिक्षक और अभिभावक पहली बार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर लगातार संपर्क में हैं। 2020 की शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) सर्वे में भी पाया गया कि लगभग एक-तिहाई नामांकित छात्रों ने सर्वेक्षण के पूर्व सप्ताह में वाट्सएप या शिक्षकों के सीधे संपर्क द्वारा कुछ शिक्षण सामग्रियां प्राप्त की थीं। पंजाब और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने तो अभिभावक-शिक्षकों की मीटिंग शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश ने 'डोर-टु-डोर' अभियान शुरू किया है, ताकि शिक्षक छात्रों के घर जाने को उत्सुक हों। अभिभावक-शिक्षक रिश्ते को संस्थागत रूप देने और स्कूल खोलने की प्रक्रिया पर संवाद के लिए ऐसे प्रयास उल्लेखनीय हैं। मगर ऐसा करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों को इनोवेशन, यानी नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा और स्थानीय प्रशासन के फैसले के मुताबिक स्कूल प्रबंधन को निर्णय लेने की आजादी देनी होगी। चूंकि दूसरी लहर अब कम हो गई है, इसलिए महीने भर का ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें माता-पिता हफ्ते में एक बार स्कूल में शिक्षकों से मिलें। इससे माता-पिता व शिक्षक स्कूल आएंगे और उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। यह उन बच्चों के अभिभावकों में भी उम्मीद पैदा करेगा, जिनके पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि स्कूल इसका उपयोग छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करने और स्कूलों को फिर से खुलने पर एक नया शैक्षणिक माहौल बनाने के अवसर के रूप में कर सकते हैं। एक बार जब आपसी भेंट व्यवस्थित हो जाएगी, स्कूल प्रबंधन कोविड-19 प्रोटोकॉल तैयार कर सकेगा, जो यथार्थवादी होगी और स्कूलों के अपने संसाधन, अपनी क्षमता और स्थानीय वास्तविकताओं से मेल खाती होगी। दूसरा कदम, नीति-निर्धारकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जमीनी हकीकत देखकर स्कूलों को खोलने (और बंद करने) का फैसला लिया जाए। इसीलिए यह निर्णय केंद्र के स्तर पर नहीं, बल्कि यथासंभव स्थानीय स्तर पर लिया जाए। कोविड-19 संक्रमण अभी आगे भी रहेगा। इसीलिए स्कूलों को तीन संभावित परिदृश्यों के लिए तैयार रहना होगा- सख्त लॉकडाउन, आंशिक गतिविधि (जिसमें शिक्षक स्कूल जा सकें, पर छात्र-छात्राओं के आने की मनाही हो) और सभी प्रतिबंधों में ढील व स्कूलों का फिर से खुलना। इन संभावनाओं के आलोक में स्कूल खुद को कैसे सुचारू बना पाएंगे, यह स्थानीय स्तर पर तय होना चाहिए। आखिर, भिन्न-भिन्न इलाकों में अलग-अलग समय पर मामले बढ़ते हैं। उचित प्रोटोकॉल तैयार करने, जिलों में समन्वय बनाने और संजीदा व अनवरत संचार के माध्यम से जनता का भरोसा तैयार करने में सरकारों (केंद्र और राज्य, दोनों) की अहम भूमिका है। मगर जब तक फैसले लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत नहीं किया जाएगा, तब तक यह संभव नहीं हो सकेगा। तीसरा कदम, वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए स्कूल स्तर पर अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। यह अधिक पैसों का मामला नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि स्कूल अपनी जरूरत व प्राथमिकताओं के मुताबिक खुद खर्च कर सकें। अभी स्कूलों को बहुत ज्यादा खर्च करने की आजादी नहीं है। उनको सालाना अनुदान ही मिलता है। मगर यह राशि प्राथमिक विद्यालयों के बजट का महज तीन से चार प्रतिशत और माध्यमिक विद्यालयों का करीब एक फीसदी होती है, और इसका उपयोग केवल नियमित रख-रखाव के लिए किया जा सकता है। साफ है, फैसले लेने के मामले में स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अधिक खर्च करने की आजादी देनी होगी। स्कूली कामकाज से स्थानीय प्रशासन को जोड़ने का अनूठा अवसर है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन को स्वास्थ्य संबंधी अनुदान देना अनिवार्य है। स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू करने के लिए इस फंड का उपयोग हो, यह फैसला लेने के लिए स्थानीय प्रशासन को सक्षम बनाया जाना चाहिए। यदि सरकारी स्कूल आगे बढ़ते हैं, तो निजी स्कूलों के भी सुरक्षित रूप से खुलने का रास्ता बन जाएगा। भारत अब अधिक समय तक स्कूलों को बंद रखने की कीमत नहीं चुका सकता। स्थानीय नवाचार और माता-पिता की सहभागिता से रास्ता तैयार हो सकता है। यह वक्त इस दिशा में आगे बढ़ने का है।

प्रवीण कुमार सिंह

अपनी भाषा को नजरंदाज करने से भावी पीढ़ियां सामाजिक एवं भाषाई धरोहर से हो जाएंगी वंचित

> लोकसभा नियमावली में संसदीय दीर्घा का संज्ञान लेने पर रोक है। राहुल जी ने दर्शक दीर्घा में बैठे युवकों का ध्यान आकर्षित किया था। कागज छीनने-फाड़ने की घटना ताजी है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या ऐसे कृत्य भी सदन के विशेषाधिकार हैं। केरल विधानसभा मामले में सर्वोच्च न्यायपीठ ने ऐसे कृत्यों को विशेषाधिकार से अलग आपराधिक कृत्य माना है। भारत की विश्व प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन संसद और विधानमंडलों का काम उत्पादक नहीं है। सदनों का व्यवधान राष्ट्रीय चिंता है। पीठासीन अधिकारियों के तमाम सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन परिणाम शून्य हैं।

हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम से ही होती है। हाल में आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कालेजों ने आगामी सत्र से अपने यहां चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए लिया गया ऐसा ऐतिहासिक फैसला है, जिस पर भावी पीढ़ियों का भविष्य टिका है। इसके साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआइसीटीई द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही बीटेक पाठ्यक्रमों को 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया भाषाओं में बीटेक विद्यार्थियों के लिए अवसरों का एक नया संसार खोलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा था कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को महत्व दिए जाने से गरीब, ग्रामीण और जनजातीय पृष्ठभूमि से आए मेधावी छात्रों में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने विद्या प्रवेश नाम के नए प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जिसका शुभारंभ भी इसी अवसर पर किया गया। इन सराहनीय कदमों का स्वागत होना चाहिए और आगामी कुछ वर्षों में इनका विस्तार भी किया जाना चाहिए, जिससे अपनी मातृभाषा में ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने का लाखों विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सके।

प्रगतिशील और दूरदर्शी नई शिक्षा नीति, 2020 में प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा को मातृभाषा में ही दिए जाने पर जोर दिया गया है, जिससे बच्चे की शिक्षा और समझ में सुधार हो। कितने ही अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि वे बच्चे जिनकी अपनी

शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होती है, वे उन बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी अन्य भाषा में हुई हो। यूनेस्को और अन्य संस्थाएं इस पर बल देती रही हैं कि मातृभाषा में सीखना, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने के लिए तथा बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है। दुर्भाग्य से कुछ अभिभावक और शिक्षक बिना जाने-बूझे अंग्रेजी के वर्चस्व पर ही बल देते हैं। परिणामस्वरूप बच्चे की अपनी ही मातृभाषा स्कूल में दूसरी या तीसरी भाषा बन जाती है।

प्रख्यात भौतिकशास्त्री और नोबल पुरस्कार से सम्मानित सर सीवी रमन ने कहा था, हमें विज्ञान को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, अन्यथा वह एक गर्व या घमंड का विषय बन जाएगा। वह ऐसा विषय नहीं बन सकेगा जिसमें हर कोई शिरकत कर सके। हमारे शिक्षा तंत्र में अभूतपूर्व प्रसार हुआ है, लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने अपने ही विद्यार्थियों की प्रगति के रास्ते में शैक्षणिक बाधाएं खड़ी कर दी हैं। हम अंग्रेजी माध्यम के चंद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के एक छोटे से बुलबुले को बनाकर ही संतुष्ट हैं, जबकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हमारी अपनी ही भाषाएं पिछड़ रही हैं। उच्चतर शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित रीति-नीति पर नजर डालें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं?

दक्षिण कोरिया में 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में शिक्षण कोरियन भाषा में ही होता है। अंग्रेजी के प्रति अभिभावकों में बढ़ते आग्रह को देखते हुए 2018 में दक्षिण कोरियाई सरकार ने स्कूलों में कक्षा तीन से पहले अंग्रेजी की पढ़ाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि विद्यार्थियों की कोरियाई भाषा में प्रवीणता कम हो रही थी। इसी प्रकार जापान में भी विश्वविद्यालयों में अधिकांश पाठ्यक्रम जापानी भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं। यही स्थिति चीन में भी है। फ्रांस और जर्मनी की शिक्षा पद्धति हमें सिखाती है कि राष्ट्र अपनी भाषा को कैसे संरक्षित रखते हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में यह अजीब है कि भारत में अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, विधि में तो स्थिति और भी खराब है, जहां स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम न के बराबर हैं। सौभाग्य से अब हम अपनी भाषा में ही अपनी आवाज पा सकेंगे। इस विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसमें हमारी भाषाओं के संरक्षण के साथ-साथ अच्छी शिक्षा भी सभी की पहुंच में हो, इसका खाका तैयार किया गया है।

हालांकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 14 कालेजों द्वारा लिया गया कदम सर्वथा सराहनीय है, लेकिन हमें और भी ऐसे ही प्रयास चाहिए। निजी विश्वविद्यालयों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। स्थानीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा लेने के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि छात्रों को स्तरीय पुस्तकें नहीं मिल पातीं, खासकर तकनीकी शिक्षा में। इस कमी का समाधान जल्द करना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों को दूरस्थ स्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री प्रायः अंग्रेजी में ही होती है, जिससे बड़ी संख्या में हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। इस दिशा में एआइसीटीई और आइआइटी, मद्रास के सहयोग से स्वयं पाठ्यसामग्री को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, मराठी, मलयालम और गुजराती आदि भाषाओं में अनुवाद कर उपलब्ध कराया जाना सराहनीय कदम है। इससे इंजीनियरिंग के छात्रों को बड़ी सहायता मिलेगी।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने का अर्थ यह नहीं कि हम कटकर अलग-थलग हो जाएं। हर व्यक्ति को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन जरूरी है कि मजबूत नींव मातृभाषा में ही पड़े। मैं मातृ भाषा बनाम अंग्रेजी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मातृभाषा के साथ अंग्रेजी का भी हिमायती हूं। आज हम परस्पर निर्भर और आपस में जुड़े हुए विश्व में रह रहे हैं। ऐसे में विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता वृहत्तर विश्व के नए द्वार ही खोलेगी। यदि हम अपनी भाषा को नजरंदाज करते हैं तो न सिर्फ ज्ञान की एक बहुमूल्य निधि को खो देंगे, बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी काट देंगे और उन्हें सामाजिक एवं भाषाई धरोहर से वंचित कर देंगे।

पहले विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा था, लेकिन अब दोनों सदनों को किए है ठप

विपक्ष एक बार फिर देश को निराश कर रहा है। पिछले छह महीने से संसद का सत्र बुलाने और कोरोना संकट सहित तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा की रट लगाने के बाद जब संसद का सत्र वास्तव में चल रहा है तो विपक्ष ने एक दिन भी कार्यवाही में शामिल होने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही नहीं, विपक्षी नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि उनकी ओर से यह पूरा सत्र वाशआउट यानी धुल चुका है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना राजनीति में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सबसे आगे है। मई की शुरुआत में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मांग की थी कि फौरन संसद का विशेष सत्र आहूत करें। तब कांग्रेस नेता ने कहा था कि सत्र बेहद आवश्यक है, क्योंकि सभी राज्यों से आने वाले तमाम सांसद अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना संकट को लेकर उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। वे लोगों को कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए समाधान चाहते हैं। कांग्रेस के 'नए मित्र' शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी विशेष सत्र की मांग दोहराई थी। जब सरकार की ओर से यह आग्रह किया गया कि पूरा सरकारी तंत्र कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में जुटा है और संसद सत्र में लोगों का जुटना खतरे से खाली नहीं तो विपक्ष ने कई दिनों तक इस पर तीखी बयानबाजी की थी।

सत्र का आगाज हुए दो सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। जो विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर में अप्रत्याशित संकटों के बीच सत्र के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा था उसने अब तक एक दिन भी कामकाज चलने नहीं दिया है। सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के नेताओं को कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई, सरकार के उपायों और भविष्य की तैयारियों का ब्योरा देने के लिए एक विशेष बैठक का आमंत्रण दिया तो कांग्रेस सहित कुछ और दलों के नेताओं ने कहा कि जब सत्र शुरू हो गया है तो अलग से बैठक क्यों? जो कहना है सरकार को संसद के पटल पर ही कहना चाहिए। इससे ही साबित हो गया था कि विपक्ष संसद सत्र को लेकर कितना गंभीर है? जबकि कोरोना पर सर्वदलीय बैठक का सुझाव भी कांग्रेस की तरफ से ही आया था। यह गंभीरता तब काफूर हो गई, जब पहले सप्ताह में ही 'विद्वानों का सदन' कहे जाने वाले राज्यसभा में एक वरिष्ठ मंत्री के हाथ से छीनकर कागज फाड़े गए। लोकसभा में तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विपक्षी सदस्य अध्यक्ष पर कागज के टुकड़े फेंकने लगे। गैलरी में बैठे पत्रकारों की ओर भी कागज फाड़कर उछाले गए। वे सदन की कार्यवाही का ब्योरा नोट करने वाले अधिकारियों को भी प्रताड़ित करने से नहीं चूके। इन तमाम नाटकीय स्थितियों के लिए विपक्ष कथित पेगासस जासूसी कांड का सहारा ले रहा है। इस विवाद पर सरकार के संबंधित मंत्री दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं। मुमकिन है विपक्ष उनके बयान से संतुष्ट न हुआ हो। अगर ऐसा था तो सबसे उत्तम फोरम राज्यसभा है, जहां नियमों के मुताबिक किसी भी मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण पूछने का प्रविधान है, लेकिन वहां तो विपक्ष का फोकस मंत्री के बयान को हंगामे में दबाने और फिर उनके हाथ से कागज छीनने में था। विपक्ष के अब तक रवैये से कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या कोरोना पर संसद का आपात सत्र बुलाना सिर्फ सरकार का ध्यान भटकाने का पैंतरा था? अगर मंशा चर्चा की थी तो विपक्ष चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते देख बहस के उलटा पड़ने की आशंका से यू-टर्न ले रहा है या विपक्ष को डर है कि विस्तृत चर्चा हुई तो उसके मुख्यमंत्रियों की कलई खुल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का दम भर रहे नेता डर रहे हैं कि बिंदुवार चर्चा से यह कथित एकता तार-तार हो जाएगी? हालांकि विपक्ष की एकता का दावा कितना खोखला है, यह आए दिन उजागर हो रहा है।

जब कांग्रेस बैठक बुलाती है तो तृणमूल के सांसद गायब रहते हैं और जब तृणमूल नेता क्षेत्रीय दलों से मिलते हैं तो कांग्रेस कन्नी काट लेती है। वास्तविकता यह है कि कोरोना के संकट काल में संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल सियासी व्यवधान का किस्सा गढ़ रहे हैं। वे एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के बजाय सरकार का काम बाधित कर रहे हैं। भयंकर बीमारी के बीच विशेष सत्र बुलाने का शिगूफा छेड़ने वाले अब संसद को एक ऐसे हवा-हवाई मुद्दे पर ठप किए बैठे हैं, जिस पर आम भारतीयों का न तो कोई ध्यान है और न ही दिलचस्पी। इससे पहले भी जनता के मूड को समझे बगैर इधर-उधर के मुद्दों पर बवाल करने की कीमत विपक्ष चुका चुका है। इस बार भी उसका यही हश्र होगा। सरकार बार-बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह दोनों सदनों के नियमों, प्रविधानों तथा चेयरमैन एवं स्पीकर के दिशा-निर्देशों के तहत कोरोना महामारी, किसान, महंगाई और बाढ़ आदि तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। कथित पेगासस जासूसी मामले पर भी सरकार ने बिना समय गंवाए संसद में बयान दे दिया, लेकिन कांग्रेस विपक्ष का 'स्वयंभू चौधरी' बनने की चतुराई में लगी है। कांग्रेस अपनी नकारात्मक सोच को संपूर्ण विपक्ष का फैसला बताकर उन विपक्षी दलों की सकारात्मक सोच को भी बंधक बनाना चाहती है, जो सदन में चर्चा और कार्य करने के पक्ष में हैं।

अपराधीकरण पर अंकुश

राजनीति के अपराधीकरण की तेज होती प्रक्रिया के मद्देनजर इस हफ्ते एक ही दिन आए सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसले ध्यान देने योग्य हैं। दोनों फैसलों की खास बात यह है कि इनमें उन पक्षों की अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली भूमिका रेखांकित होती है, जिनसे उस पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की जाती है। पहले मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया कि मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस राज्य सरकारें अपने स्तर पर वापस नहीं ले सकतीं। उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी होगी। यह निर्देश जारी करने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अमाइकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्य सरकारें ऐसे मामले वापस लेने की कोशिश में हैं। एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम प्रमुख दलों पर अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को सही ढंग से उजागर न करने के कारण जुर्माना लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट के ही फरवरी 2020 में दिए गए एक फैसले से जुड़ा है, जिसके मुताबिक प्रत्याशियों को अपनी डीटेल्स या तो चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन पत्र भरे जाने की पहली तिथि से कम से कम दो हफ्ते पहले तक अपलोड कर देनी थीं।

अदालत के सामने लाई गई अवमानना की शिकायत में कहा गया कि संबंधित दलों ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान अदालत के इस आदेश का ढंग से पालन नहीं किया। कोर्ट ने इस शिकायत को सही पाते हुए न केवल दोषी दलों पर जुर्माना लगाया बल्कि अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए यह भी कहा कि आगे से सभी दलों को प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के अंदर न केवल उनकी सूचना अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी बल्कि दो समाचारपत्रों में भी छपवाना होगा। हालांकि इस मसले पर जब-तब यह राय भी प्रकट की जाती रही है कि शासन और पुलिस द्वारा अक्सर कई झूठे मामले राजनीतिक इरादों के तहत भी दर्ज कर लिए जाते हैं, जो आगे चलकर अदालतों में खारिज हो जाते हैं।

ऐसे में पुलिस केस के आधार पर किसी उम्मीदवार के बारे में क्यों राय बनाई जाए? लेकिन समझना होगा कि इन आदेशों में न तो उम्मीदवारों के चुने जाने के अधिकार पर कोई रोक लगाई गई है और न ही चुनने के वोटरों के अधिकार को सीमित किया गया है। सिर्फ यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि वोटरों से जरूरी तथ्य न छुपाए जाएं। राजनीतिक दलों के इसी ढीले-ढाले रवैये के चलते संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पिछले चार आम चुनावों के दौरान 24 फीसदी से बढ़कर 43 फीसदी तक पहुंच गई। जाहिर है, राजनीति के अपराधीकरण को अब और हल्के में लेना लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

वास्तविक लोकतंत्र में नेताओं को संकीर्ण राजनीति का करना पड़ता है परित्याग

> मैं लोकतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य शासन पद्धति की पैरवी नहीं करता। वास्तविक लोकतंत्र विवेक की मांग करता है, जिसमें सभी वर्ग के नेताओं को संकीर्ण राजनीतिक हितों का परित्याग करना पड़ता है। उसे घपलेबाजों पर विराम लगाना होता है। ऐसे में विरोध पर अड़े राजनीतिक वर्ग को मौजूदा सरकार का समर्थन करने का जज्बा दिखाना चाहिए, जो मतदाताओं के कोप की परवाह न करते हुए सुधारों की राह में अपनी राजनीतिक पूंजी निवेश करने का साहस दिखा रही है। चलिए ऐसे भारत के निर्माण में जुटते हैं, जिस पर हम सभी हमेशा के लिए गर्व कर सकें।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की स्थापना के शताब्दी समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। ताकतवर देशों को उन्होंने जहां आंखें दिखाई वहीं अपने पिट्ठू बन चुके देशों को एक प्रकार का लालीपाप दिया। उनके इन तेवरों के पीछे चीन की अर्थव्यवस्था में आई जबरदस्त तेजी एक अहम ताकत है। करीब 14 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की हैसियत के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके बाद पांच ट्रिलियन डालर वाली जापानी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों के बीच अंतर की खाई खासी चौड़ी है। चीनी अर्थव्यवस्था 1979 तक महज 202 अरब डालर की थी। उसने 40 वर्षों में इतनी तेज वृद्धि की है। भारत को देखें तो यही लगेगा कि चीन के मुकाबले हम कितना पीछे रह गए और वह भी तब जब पिछली सदी के नौवें दशक में चीन ने जब आर्थिक सुधार शुरू किए थे तब भारतीय अर्थव्यवस्था उससे कहीं बेहतर स्थिति में थी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन चाहता है कि भारत उसकी श्रेष्ठता को स्वीकारे, जो स्वाभिमानी भारतीय राज्य कभी स्वीकार नहीं कर सकता। समय-समय पर भारत को उन छोटे देशों से भी चुनौती मिलती रहती है जिनकी न केवल सामरिक, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी कोई खास हैसियत नहीं है। वे इसी धारणा से भारत की परेशानियां बढ़ाने का मुगालता पाल लेते हैं कि उसकी हिचकोले खा रही अर्थव्यवस्था और कोलाहल भरे लोकतंत्र के कारण उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। आर्थिक रूप से कुछ शक्तिशाली राष्ट्र भी उन्हें इसके लिए उकसाते हैं।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मैडिसन ने विश्व के आर्थिक इतिहास से जुड़ा एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जिसकी वैश्विक जीडीपी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। नीदरलैंड से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक अधिकांश यूरोपीय देशों ने भारत में धन की लालसा में ईस्ट इंडिया कंपनियां स्थापित कीं। धन की लिप्सा ने सज्जन व्यापारियों को दुष्ट उत्पीड़कों में बदल दिया, जिन्हें भारत में लूट-खसोट के लिए अपने-अपने देश की सरकारों से समर्थन मिला। आखिरकार उनकी राष्ट्रीय सेनाओं ने टुकड़ों में बंटी भारतीय रियासतों को परास्त कर दिया। उनकी 'बांटो और राज करो' वाली नीति और बारूद का इस्तेमाल इसमें मददगार रहे। कभी व्यापारी के रूप में आए विजेता बन बैठे और उपमहाद्वीप को अपने कब्जे में लेने के लिए एकजुट हो गए। स्वतंत्रता के लिए करीब एक सदी तक चले संघर्ष के बाद विदेशी हमारा देश तो छोड़ गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा भारत छोड़ा जो आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका था, जहां गरीबी और विषमता का बोलबाला था और उद्योग-धंधे चौपट हो चुके थे।

प्रखर देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने गरीबी और आर्थिक विषमता मिटाने के संकल्प के साथ देश की बागडोर संभाली। उनमें से कई सेनानी ऐसे थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी आकर्षक पेशेवर जिंदगी और वैभव संपन्न जीवन शैली को भी त्याग दिया। अपने 74 वर्ष की राजनीतिक स्वतंत्रता के इतिहास में भारत कई राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाक्रमों का गवाह बना। इसमें तेज जीडीपी, प्रति व्यक्ति वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और सियासी कामयाबियों का दौर भी रहा। इसके बावजूद भारत अभी भी परिणामोन्मुखी राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने से दूर है। जब भी हमें कोई चुनौती मिलती है तो शक्तिशाली देशों का समर्थन लेने के लिए हमारी कूटनीतिक कवायदें यकायक तेज हो जाती हैं। हाल के दौर में मीडिया के कुछ हलकों में 30 साल पहले लाइसेंस-परमिट राज की समाप्ति और आर्थिक सुधारों की शुरुआत से संबंधित विमर्श को धार दी गई। हालांकि इनमें से कुछ बाधाओं की कभी पूरी तरह विदाई नहीं हुई।

नीति नियोजन से जुड़े कुछ लोगों ने इस दौरान यह भी स्मरण किया कि आखिर किन मोर्चों पर अवसर गंवा दिए गए। दिलचस्प यह है कि जिस दौर को उन्होंने अवसर गंवाने वाला बताया, उसी दौरान उनमें से कुछ लोग नीति निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय भी रहे। उन्होंने ढांचागत सुधारों और देश की आर्थिक वृद्धि में निरंतर बढ़ोतरी की दिशा में कोई मदद नहीं की। असल में राजनीतिक साहस का अभाव इसकी बड़ी वजह रही कि पता नहीं मतदाता इन सुधारों से होने वाली मुश्किलों को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इसके बजाय अपनी सरकारों की मियाद बढ़ाने के लिए चुनावी खैरात बांटने की होड़ लग गई। इससे अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होता गया। चीन सहित अधिकांश शक्तिशाली देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर, गरीबी को हटाकर और बेहतरी के व्यापक पहलुओं को स्थापित करके ही प्रतिष्ठा पाई और शक्तिशाली देशों में अपनी जगह बनाई। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता। भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण और उत्पादकता में वृद्धि से ही ऊंचा आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।

हमारे पास पूंजी की आपूर्ति तंग है। तकनीक में भी यही स्थिति है। ऐसे में ढांचागत सुधार अनिवार्य हो गए हैं ताकि संसाधनों की गुणात्मक वृद्धि कर लाभ उठाया जा सके। लोकतंत्र में यह दोनों पक्षों के समर्थन की मांग करता है। अफसोस की बात है कि भारत में किसी आपदा या युद्ध से इतर किसी स्थिति में ऐसा समर्थन संभव नहीं दिखता। राजनीतिक लाभ विवेक पर हावी हो रहा है। वे सभी अर्थव्यवस्था विशेषकर पूर्वी एशियाई, जिन्होंने विगत 50 वर्षों के दौरान चमत्कार करके दिखाया है, उनमें ढांचागत सुधारों की अवधि के दौरान अगर तानाशाही नहीं तो कम से कम अधिनायकवादी शासन अवश्य था। उनमें से कुछ देशों में तो अभी तक यही व्यवस्था कायम है। मैं लोकतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य शासन पद्धति की पैरवी नहीं करता। वास्तविक लोकतंत्र विवेक की मांग करता है, जिसमें सभी वर्ग के नेताओं को संकीर्ण राजनीतिक हितों का परित्याग करना पड़ता है। उसे घपलेबाजों पर विराम लगाना होता है। ऐसे में विरोध पर अड़े राजनीतिक वर्ग को मौजूदा सरकार का समर्थन करने का जज्बा दिखाना चाहिए, जो मतदाताओं के कोप की परवाह न करते हुए सुधारों की राह में अपनी राजनीतिक पूंजी निवेश करने का साहस दिखा रही है। चलिए ऐसे भारत के निर्माण में जुटते हैं, जिस पर हम सभी हमेशा के लिए गर्व कर सकें।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ डीए, एरियर के साथ मिलेगी बढ़ी सैलरी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के सम्बंध में बढ़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से 28त्न की बढ़ोतरी के साथ ष्ठ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वकीलों के लिए भी योजना का ऐलान किया। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख मिलेंगे,पहले मिलते थे 1.5 लाख मिलते थे।

कर्मचारियों व पेंशनर्स को अब 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए, डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।

सीएम योगी ने की कई अन्य घोषणा –सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए भी विधानसभा में कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा सरकार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन देगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए का एक कोष गठित किया गया है। इसके अलावा यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में आने-जाने का भत्ता देगी।

वार्ड पार्षद के बेटे का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल, कानून की उड़ाई धज्जिया

पटना । पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके के एक वार्ड पार्षद के बेटे का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो गया है। एक बर्थडे पार्टी में वार्ड पार्षद का रईसजादा गोली चलाते दिख रहा है। वीडियो में उसने अपना नाम लिखा है। साथ ही स्ट्राइकिंग हंटर ऑफ पटना, कोई नहीं है टक्कर में... भी वीडियो पर लिखा आ रहा था। युवक के साथ उसके अन्य दोस्त भी शामिल हैं। गाने की धुन पर युवक पहले डांस कर रहा है फिर एकाएक हवाई फायरिंग कर उसने कानून की धज्जियां उड़ा दीं। उसके आसपास तीन से चार लड़के भी मौजूद हैं। यह वीडियो हाल का ही है। स्ट्राइकिंग हंटर ऑफ पटना नाम के गैंग को चलाने वाले वार्ड पार्षद के बेटे के फायरिंग करने के दौरान किसी ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया।

उस वीडियो को गोली चलाने वाले ने भी सोशल साइट्स पर अपलोड किया लेकिन तब तक वह वायरल हो चुका था। खबर है कि अक्सर वह हर्ष फायरिंग कर इलाके में दहशत पैदा कर देता है। पूर्व में भी उस पर बुद्धा कॉलोनी थाने में एक अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच का विषय यह है कि आखिर वार्ड पार्षद के बेटे के हाथ में हथियार कहां से आया?

गोंडा पहुंचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र, कहा; अफगानिस्तान में फंसे हर धर्म के लोगों की सरकार करेगी मदद

गोंडा । केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र ने कहा कि अफगानिस्तान मामले पर सरकार की पूरी नजर है। अफगानिस्तान में अगर कोई अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वह भारत सरकार के दूतावास से संपर्क कर सकता है। वह चाहे किसी भी धर्म व किसी भी देश का हो। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार लंबी अवधि का वीजा देने का प्रयास कर रही है। गुरुवार को गोंडा में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार आमजन के हितों को ध्यान में रखकर सबका साथ सबका विकास की नीति के अनुरूप काम कर रही है। उन्?होंने कहा कि बीजेपी समाज के हर वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर स्तर पर कर रही है। अजय मिश्र ने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में बताया। कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रि मंडल के विस्तार के बाद से सदन शुरू हो गया था। इस बार विपक्षी दलों ने सदन को चलने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र ने कहा कि जो भी व्यक्ति देश व संविधान के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है उस पर सरकार की पूरी नजर है। सरकार अपने स्तर से उस पर कार्रवाई भी कर रही है। शायर मुनव्वर राणा के बयान पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। अब्बाजान को लेकर चल रहे हंगामे पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शब्दों को भी हिंदू-मुस्लिम की दृष्टि से देखती है।

मौसम विभाग ने अगले सात दिन के लिए जारी की चेतावनी, जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

जमशेदपुर । झारखंड के जमशेदपुर शहर के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार दो दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। गुरुवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह-जगह पर पानी का जमाव हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर शहर में 23 एमएम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, शहर में अगले सात दिनों तक रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के साथ-साथ गर्जन भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को भी अलर्ट होने की जरूरत है।

बिना मतलब घर से निकलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से कम से कम घर से निकलने की अपील की जा रही है। बाजारों में अधिक भीड़ होने की वजह से संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसे लेकर हर कोई चिंतित है। अमेरिका सहित अन्य देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। इस दौरान वहां रोजाना एक लाख से अधिक नए मरीज व एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो रही है, जो चिंता का विषय है।

बिना मास्क के घूम रहे लोग-बारिश के दौरान देखा जा रहा है कि लोग रैन कोट तो पहन रहे हैं लेकिन मास्क पहनना भूल जा रहे हैं, जो अधिक खतरनाक साबित हो सकता है।

सीएम योगी का विपक्ष पर वार, बोले- हम माफियाओं को सिर पर ढोते नहीं चलते, गुंडों के घर गिराकर गरीबों को बसा रहे

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार माफियाओं को सिर पर लेकर नहीं घूमती। हमने माफियाओं से 1500 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की। यह सम्पत्ति गरीबों को लूटकर बनाई गई थी। गरीबों को लूटकर जो भवन बनाए गए थे, हम उन्हें गिराकर वहां गरीबों-दलितों के लिए घर बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष के लोग अयोध्या की तरफ झांकते नहीं थे लेकिन आज हर कोई कह रहा है कि राम हमारे हैं। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हमारा भाव, हमारा दर्शन और जीवन का हिस्सा है। यह हमारी कार्यपद्धति में पग-पग पर दिखता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि आर्थिक योजनाओं और आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी मिलना चाहिए। हमने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सीएम ने कहा कि यह पहली महामारी है जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं मरा। हमें महामारी को तो स्वीकार करना होगा नहीं तो बीमारी के उपचार के लिए और बीमारी से बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को तो गरीबों को अन्न दिया जाना भी बुरा लग रहा है। झोलों में अनाज वितरण को भी गरीबों का मजाक बता दिया। यह साफ दिख रहा है कि विपक्ष को जमीन पर चलने की आदत नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा काफी बढ़ गया। वर्ष 2015-16 में ढाई लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 2016-17 में 2.40 लाख करोड़ का बजट आया। आज हम करीब छह लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल रहे हैं। बड़ी सोच और बड़े कार्यों के साथ बजट का दायरा भी बढ़ा है।

24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में दो-तीन लाख करोड़ रुपए का बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थी। वैसी संकीर्ण सोच से विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के न जाति, न मत-मजहब, न क्षेत्र न भाषा, सबका साथ-सबका विश्वास के आधार पर जो कार्यक्रम किए उसका नतीजा ये रहा कि बजट का दायरा बढ़ गया। पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है।

प्रदेश की जीएसटी भी पांच वर्ष पहले 10-11 लाख करोड़ के आसपास थी आज 20-21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हम कहां थे। आबादी में नंबर एक होने के बावजूद जातीय-सांप्रदायिक दंगों, भ्रष्टाचार, विकास में पीछे रहने के कारण अर्थव्यवस्था में छह नंबर पर था। पिछले साढ़े चार वर्षों के परिश्रम के चलते उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर दो पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों के अवसर बढ़े हैं। व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए इस पर हमने व्यापक संशोधन किए, नीतियां बनाई जिसके परिणाम सामने हैं। अगर दुनिया में भारत निवेश का सबसे अच्छा देश है, तो देश में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उ.प्र. 16वें स्थान से दूसरे स्थान पर आया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सबके लिए काम किया। अब तक यूपी में सात करोड़ लोगों के टेस्ट हुए। छह करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। रोज चार लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। यूपी में रिकवरी रेट सबसे अच्छा है।

यूजी-पीजी और डिप्लोमा के एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्ट फोन देगी सरकार

लखनऊ । मिशन-2022 की तैयारी में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। सीएम ने विधानसभा में कहा सरकार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन देगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए का एक कोष गठित किया गया है।

राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हमने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सीएम ने कहा कि यह पहली महामारी है जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं मरा। हमें महामारी को तो स्वीकार करना होगा नहीं तो बीमारी के उपचार के लिए और बीमारी से बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा।

अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम ने विपक्ष पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तो गरीबों को अन्न दिया जाना भी बुरा लग रहा है। झोलों में अनाज वितरण को भी गरीबों का मजाक बता दिया। यह साफ दिख रहा है कि विपक्ष को जमीन पर चलने की आदत नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा काफी बढ़ गया। वर्ष 2015-16 में ढाई लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 2016-17 में 2.40 लाख करोड़ का बजट आया। आज हम करीब छह लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल रहे हैं। बड़ी सोच और बड़े कार्यों के साथ बजट का दायरा भी बढ़ा है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में दो-तीन लाख करोड़ रुपए का बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थी। वैसी संकीर्ण सोच से विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के न जाति, न मत-मजहब, न क्षेत्र न भाषा, सबका साथ-सबका विश्वास के आधार पर जो कार्यक्रम किए उसका नतीजा ये रहा कि बजट का दायरा बढ़ गया। पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार माफियाओं को सिर पर लेकर नहीं घूमती। हमने माफियाओं से 1500 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की। यह सम्पत्ति गरीबों को लूटकर बनाई गई थी। गरीबों को लूटकर जो भवन बनाए गए थे, हम उन्हें गिराकर वहां गरीबों-दलितों के लिए घर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष के लोग अयोध्या की तरफ झांकते नहीं थे लेकिन आज हर कोई कह रहा है कि राम हमारे हैं।

बस्ती में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए आशिक मिजाज दारोगा पर एक्शन, एसपी ने सस्पेंड कर सीओ को सौंपी जांच

बस्ती । बस्ती में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए दारोगा के खिलाफ एक्शन हो गया है। बस्ती के एसपी ने दारोगा पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी ने मामले की जांच एएसपी और सीओ को सौंप दी है। उन्होंने कहा है जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि बस्ती के दुबौलिया थाने पर तैनात आशिक मिजाज दारोगा को बुधवार/गुरुवार की देर रात ग्रामीणों ने एक युवती के घर से निकलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। ग्रामीणों ने दारोगा पर रंगरेलियां मनाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू किया तो नाराज दारोगा ने सरकारी पिस्टल से फायर कर दिया। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने जमकर धुनाई के बाद दारोगा को खंभे से बांध दिया और लाठी-डंडों से पीटा। भोर में करीब 4 बजे सूचना पर पहुंचे दुबौलिया थानाध्यक्ष दारोगा को साथ ले गए। दारोगा की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दुबौलिया थाने के हल्का नंबर-2 का दारोगा अशोक कुमार चतुर्वेदी चिलमा बाजार में किराए पर कमरा लेकर रहता है। करीब दो साल से दुबौलिया थाने पर ही तैनात दारोगा अशोक की आशिक मिजाजी की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। करीब चार महीने पहले ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से उसकी गलत हरकतों की शिकायत की थी। थाने से हटाए जाने के बाद पता नहीं कैसे फिर उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि फिर से दुबौलिया आ गया। मनचला दरोगा अशोक बुधवार की देर रात पल्सर बाइक से थाना क्षेत्र के ऊंजी गांव पहुंचा और एक घर में घुस गया।

पहले से ही नजर गड़ाए ग्रामीण बाहर लाठी-डंडा लिए उसके निकलने का इंतजार करते रहे। भोर में करीब 3 बजे दारोगा अशोक बाहर निकला तो खुद को घिरा देख अपनी सरकारी पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने जमकर पिटाई के बाद उसे खंभे से बांध दिया और लाठी-डंडों से धुना। ग्रामीणों की ही सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष मनोज त्रिपाठी किसी तरह उसे ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने ले गए। इस बारे में बस्ती के एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या दारोगा पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से कप्तान ने निलंबित कर दिया है। एएसपी और सीओ को जांच के लिए गांव भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

वार्ड ब्वाय ने अस्पताल से चुरा ली वैक्सीन, गांव में पैसे लेकर कर रहा था वैक्सीनेशन

मऊ । आजमगढ़ जिले के हरैया स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात वार्ड ब्वाय के घर से पुलिस ने कोरोना वैक्सीन की 25 वायल बरामद की है। यह गांव में पैसे लेकर लोगों को वैक्सीन लगा रहा था। वार्ड ब्वाय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

आजमगढ़ जिले के हरैया स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात वार्ड ब्वाय के घर से पुलिस ने कोरोना वैक्सीन की 25 वायल बरामद की है। यह गांव में पैसे लेकर लोगों को वैक्सीन लगा रहा था। वार्ड ब्वाय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

भदसामानोपुर निवासी राहुल राय आजमगढ़ जिले के हरैया स्वास्थ्य केंद्र पर संविदा पर वार्ड ब्वाय के पद पर तैनात है। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान को जानकारी मिली कि पैसे लेकर टीकाकरण किया जा रहा है। एसपी ने कोपागंज पुलिस को मौके पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस की छापेमारी में 25 वायल बरामद हुआ है। वार्ड ब्वाय को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की जगह लगा रहा था गैस की सुई

इसी तरह कुछ दिन पहले वाराणसी के एक गांव में कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाकर वसूली करने का मामला सामने आया था। यहां एक स्वास्थ कर्मचारी गांव वालों से बीस-बीस रुपये लेकर उन्हें यह इंजेक्शन लगा रहा था।

काशीपुर गांव में पीएचसी पर तैनात हेल्थ सुपरवाइजर मोहन राम लोगों से 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेकर इंजेक्शन लगा रहा था। उसका दावा था कि वह कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगा रहा है। गांव के एक युवक ने बिना रजिस्ट्रेशन टीका लगाने के बाद प्रमाण पत्र मांगा तो वह धौंस देने लगा। जिस पर उसे शक हुआ और उसने सिंधोरा थाने में सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसएसआई संजीत बहादुर सिंह ने इंजेक्शन के वायल को जब्त करके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पिंडरा डॉ एचसी मौर्य को सूचना दी। चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद बताया कि इंजेक्शन डेक्सोना और एसीलॉक है। डेक्सोना एक एंटी एलर्जिक, जबकि एसीलॉक गैस का इंजेक्शन है। थाने में पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि धन कमाने की नीयत से वह कई दिनों से गांवो में घूम-घूमकर लोगों को इंजेक्शन लगाकर 20 से 50 रुपये तक वसूल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक आला, एक वायल डेक्सोना, एक एम्पुल रेंटेडिन व अन्य दवाएं बरामद हुई हैं। पुलिस ने पिंडरा पीएचसी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी बीरबल की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेज दिया।

एक सप्ताह से लगा रहा था इंजेक्शन – कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाकर वसूली करने वाला आरोपित हेल्थ सुपरवाइजर सिंधोरा थाना क्षेत्र के गड़खडा गांव का निवासी है। ग्रामीण रत्नेश पांडेय ने बताया कि गत एक सप्ताह से काशीपुर स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के गांवो में घूम कर कोविशिल्ड के नाम फर्जी इंजेक्शन लगा रहा था और 20 से 50 रुपये की वसूली कर रहा था। आरोपित ने जितने लोगों को कोरोना का टीका लगाया है उन लोगों की पुलिस सूची तैयार कर रही है। आरोपी जिस गांव में भी लोगों को टीका लगाने गया है वहां पर टीम जाएगी और लोगों की सूची तैयार करेगी। उन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा।

अनुपूरक बजट पर चर्चा में रामगोविंद चौधरी बोले- सरकार नहीं चला रही है सदन

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच में गुरुवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। विधानमंडल के मानसून सत्र में गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सदन में तथा सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के हंगामा करने के बीच में राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार सदन नहीं चला रही तो हम जनता का समाना कैसे करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछली कार्यमंत्रणा में जो मद 24 अगस्त के लिए निर्धारित थे, वह आज ही ले लिए गए। इससे साफ है कि सरकार आज ही भाग जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। इससे सबसे ज्यादा समस्या तो हमें है। बाढ़, बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता के मुद्दे कहां उठाएं। जनता को क्या कहेंगे कि उनकी बात हमने कहां उठाई। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर रोजगार और विकास के झूठे प्रचार के आरोप लगाए। इससे पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।

जातीय जनगणनाः तेजस्वी का सीएम पर हमला, पूछा- नीतीश सहयोगी हैं या पीएम मोदी के गुलाम?

पटना । बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए बुधवार को पूछा कि नीतीश सहयोगी हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलाम। यादव का यह बयान तब आया जब उनसे जाति आधारित जनगणना पर टिप्पणी करने को कहा गया। राजद जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है।

तेजस्वी ने पूछा, हम 4 अगस्त से प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं ताकि जाति आधारित जनगणना के बारे में बात कर सकें। लेकिन पीएम के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय नहीं है। नीतीश कुमार सहयोगी हैं या पीएम के गुलाम बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं और वे जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उनसे इसपर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा है।

हालांकि सीएम ने कहा कि वे पीएम मोदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। 16 अगस्त को उन्होंने कहा, जाति आधारित जनगणना कराने की मांग के संबंध में लिखा मेरा पत्र प्राप्त होने की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दी है। हम अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने कहा था कि 2019 में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जाति आधारित जनगणना के संबंध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। राज्य विधानसभा में 2020 में एक बार फिर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

राजद नेता ने बुधवार को राज्य में राजद के विस्तार को लेकर झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, मैं पार्टी का काम सुनिश्चित करने के लिए हर महीने के तीसरे रविवार को झारखंड का दौरा करूंगा। पिछली बार हमने कम अंतर से कुछ सीटें गंवाई थीं। हमने मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। तेजस्वी ने बताया कि संजय यादव झारखंड में राजद के प्रधान महासचिव हैं। प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए राजद नेता ने कहा, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य में एक भी केंद्रीय समिति नहीं भेजी गई है। पीएम ने बिहार में बाढ़ संकट से मुंह मोड़ लिया है।

जून से अगस्त के बीच मुजफ्फरपुर का अहियापुर थाना दूसरी बार बाढ़ग्रस्त, कई मुहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी

मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक दूसरी बार उफान पर है। इस वजह से मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों में दूसरी बार बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। शेखपुर, आश्रम घाट लकड़ीढाई और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के इलाके में बाढ़ का पानी मुहल्लों में घुस गया है। नदी के बांध के भीतर बड़ी संख्या में झोपड़ियां डूब गयी हैं वहीं अहियापुर थाने में जून के बाद फिर से पानी भर गया है।

दूसरी बार बाढ़ आ जाने से लोग हैरत में हैं। शेखपुर से पलायन भी शुरु हो गया है। पक्का मकान वाले उपर शिफ्ट करने की तैयारी में हैं तो कच्चा मकान वालों नें उंचे स्थानों पर तम्बु लगाना शुरु कर दिया है। बारिश के जलजमाव के बीच बाढ़ का पानी मुहल्लों में भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी तटबंध में बने सभी स्लूइस गेट पर नगर निगम नें चौकसी बढा दिया है।

दूसरी बार बाढ़ पर एसडीओ पूर्वी डॉ कुन्दन कुमार नें बताया है कि हालात अभी नियंत्रण में हैं। मुशहरी सीओ को बाढ़ पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। अहियापुर थाना के एसएचओ सुनील कुमार रजक नें कहा है कि दूसरी बार थाना परिसर और रास्ते पर पानी भर गया है। पुलिसकर्मी और आम लोगों को थाना पर आने जाने में कठिनाई हो रही है। बाढ़ की वजह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।

बीजेपी के बाद अब जेडीयू के मंत्री भी करेंगे जनसुनवाई, जानें किस दिन कौन से मंत्री सुनेंगे आपकी समस्या

पटना । जदयू के प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में चार दिन मंत्रीगण कार्यकर्ताओं और आमलोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका जल्द-से-जल्द निराकरण कराएंगे। कौन मंत्री किस दिन उपस्थित रहेंगे, यह भी तय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह व्यवस्था अगले सप्ताह से शुरू की जा रही है।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के विकास कार्यक्रमों को और तेज गति से लागू करने और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान करने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अगले सप्ताह से मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 11.30 बजे से पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों से संवाद स्थापित करेंगे मंत्रीगण। इसके लिए बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है, ताकि निर्धारित तिथि और समय पर वे प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहें।

किस दिन कौन मंत्री रहेंगे

मंगलवार : शिक्षा व संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान

बुधवार : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज

गुरुवार : ऊर्जा और योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, परिवाहन मंत्री शीला मंडल और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी

शुक्रवार : भवन निर्माण मंत्री अशौक चौधरी, जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा और विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह

समस्तीपुर में साइकिल समेत मजदूर पानी भरे गड्ढे में डूबा, मौत

समस्तीपुर । समस्तीपुर में बाढ़ के पानी में एक साइकिल सवार गिर गया जिसमें डूब कर उसकी मौत हो गई। घटना विद्यापति नगर के कांचा गांव की है। मृतक की पहचान मनियारपुर पतैली के स्वर्गीय भोला महतो के पुत्र मोहन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विद्यापति नगर के सीओ अजय कुमार ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मृतक की पत्नी पिंकी देवी ने घटहो ओपी पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि मोहन महतो मजदूरी करता था। सुबह 6 बजे वह काम पर जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में गड्ढे में भरे पानी में डूब कर मोहन की मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कांचा गांव के वार्ड-7 में सड़क बन रही है। निर्माणाधीन सड़क पर रखे गए गिट्टी पर मोहन की साइकिल फिसल गई और वह साइकिल समेत सड़क किनारे के गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में बाढ का पानी भरा है। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने मोहन महतो को गिरते हुए देख लिया था। लोगों नें मिलकर उसे बाहर निकाला। लेकिन गहरे पानी से जब तक उसे निकाला जाता तब तक वह दम तोड़ चुका था। सीओ अजय कुमार ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तेजप्रताप यादव ने किया इशारा, कौन हैं वो प्रवासी सलाहकार, जो पैदा कर रहे हैं राजद और लालू परिवार में मतभेद

पटना । पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की अंदरुनी कलह सामने आ रही है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप के बीच मतभेद भी सामने आ चुके हैं। कल जगदानंद सिंह ने राजद छात्र इकाई के अध्यक्ष आकाश यादव को हटा दिया था। इसके बाद नाराज तेजप्रताप ने अपने ट्वीट में किसी प्रवासी सलाहकार का जिक्र किया था। आज एक बार फिर उन्होंने इसी सलाहकार का जिक्र करते हुए उसे पार्टी और लालू परिवार के बीच मतभेद पैदा करने वाला बताया है।

तेजप्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा, जिस प्रवासी सलाहकार के इशारो पे पार्टी चल रही वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता, वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनायेगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है।

तेजप्रताप के इस ट्वीट से कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आखिर ये प्रवासी सलाहकार कौन हैं। पहले माना जा रहा था कि तेजप्रताप ने तेजस्वी को प्रवासी सलाहकार कहकर निशाना साधा है। हालांकि आज के ट्वीट से इस बात के साफ संकेत मिल गए हैं कि ये कोई और है जो पार्टी और परिवार के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

आकाश यादव को हटाने पर भड़के थे तेजप्रताप– अपने करीबी आकाश यादव को राजद की छात्र इकाई से हटाए जाने पर हसनपुर से विधायक तेजप्रताप यादव नाराज हो गए थे।

उन्होंने ट्वीट कर कहा था, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए की पार्टी संविधान से चलती है और आरजेडी का संविधान कहता है की बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ हुआ।

दिलाई सदभावना दिवस की प्रतिज्ञा

गुरुवार को भोपाल स्थित मंत्रालय वल्लभ भवन में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। सभी ने प्रतिज्ञा ली कि जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। साथ ही यह प्रतिज्ञा भी ली कि हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाएंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, मलय श्रीवास्तव, एसएन मिश्रा, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, संजीव कुमार झा सहित मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं दूसरे चित्र में आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने जनसंपर्क संचालनालय में अधिकारी कर्मचारियों को सद्भावना दिवस पर प्रतिज्ञा दिलाई।

अब 13 सितंबर को कलेक्टर-कमिश्नरों के कामकाज का फीडबैक लेंगे सीएम

23 को होने वाली बैठक स्थगित

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के आला मैदानी अफसरों में शुमार कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के कामकाज की समीक्षा के लिए 23 अगस्त को बुलाई गई बैठक स्थगित हो गई है। अब यह बैठक 13 सितंबर को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन अफसरों के कामकाज का फीडबैक लेंगे।

इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी से मिले फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री चौहान प्रशासनिक सर्जरी को अंजाम देंगे। हालांकि 13 सितंबर को होने वाली बैठक के लिए फिलहाल अलग से अभी एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसे भी बाद में जारी किया जाएगा। प्रदेश के नौ जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के बाद ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में आला मैदानी अमला अब प्रभावित लोगों को राहत देने के काम में जुट गया है। यह काम इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला बना हुआ है। इसे देखते हुए ही 23 अगस्त की बैठक को टाल दिया गया है, जिससे कि इन जिलों में राहत के कार्य प्रभावित नहीं हो।

बेटे के बैंक खाते में पैसा जमा कराया, अब आईएफएस मीणा निलंबित

वन विभाग ने जारी किए आदेश

भोपाल (एजेंसी)। भारतीय वन सेवा के 1994 बैच के अधिकारी मोहनलाल मीणा को अपने बेटे के खाते में अपने अधीनस्थ पर दबाव डालकर जबरन पैसा जमा कराना आखिर भारी पड़ गया। राज्य सरकार ने गुरुवार को उन्हें निलंबित कर दिया है। मीणा तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक बैतूल के पद पर पदस्थ रहे हैं।

राज्य सरकार ने पदस्थापना अवधि में अपने अधीनस्थ को अपने पुत्र के बैंक खाते में पैसा जमा करने के मामले में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। राज्य सरकार ने माना है कि राशि जमा करने के लिए निर्देशित करना और वह राशि जमा होना धनराशि संव्यवहार की श्रेणी में आता है जो कि अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम के विपरीत है। इस मामले में वन विभाग ने जांच दल गठित किया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में मोहनलाल मीणा को अनुचित आचरण का प्रथम दृष्टि दोषी पाया है। इसलिए तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक बैतूल वृत्त, वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , मुख्यालय भोपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मीणा का मुख्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल रहेगा।

कमलनाथ ने कोरोना गाइडलाइन के दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप

भोपाल, (एजेंसी)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में कोरोना गाइडलाइन के पालन में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।

श्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि प्रदेश में हजारों बेरोजगार युवा रोजगार मांगें, तो उन पर लाठियां बरसायी जाती हैं, प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है, वहीं हजारों चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र मांगें, तो उन्हें भी कोरोना गाइडलाइन याद दिलायी जाती है। उन पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है'वहीं धार्मिक पर्वों पर भी तमाम प्रतिबंध लागू और वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राएं तमाम नियम कायदों व गाइडलाइन को ताक पर रखकर भव्य तरीके से जारी।'श्री कमलनाथ ने कहा'यात्रा मार्गों पर भव्य स्वागत, ढेरों स्वागत मंच, स्वागत द्वार, होर्डिंग, पोस्टरों, तमाम तामझाम से भरी यह भव्य यात्राएं ऐसे समय निकाली जा रही हैं, जब प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है।' राजधानी भोपाल में कल चयनित शिक्षकों ने यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास धरना देकर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं ने भी नीलम पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया था। जब ये लोग रोशनपुरा चौराहे की ओर बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोक लिया था। इसको लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति बन गयी थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में दर्जनों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की हैं।

तय कीमत से ज्यादा की वसूली और जहरीली शराब पर अंकुश लगाने की तैयारी

अब शराब खरीदने पर बिल भी मिलेगा जनाब

प्रदेश में एक सितंबर से मिलने लगेगी रसीद

मदिरा दुकानों पर अधिकृत मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करना होगा

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में शराब बेचने पर खरीददार को कैश मेमो यानी रसीद भी मिलेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि उसने कौन सी शराब खरीदी है और उसकी कीमत क्या है। प्रदेश में जहरीली शराब की बिक्री और मनमाने दामों पर बेचने की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए यह कवायद की गई है। हाल ही में मंदसौर जिले में जहरीला शराब से मौत के मामले की जांच के लिए गठित जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट में शराब की बिक्री पर कैश मेमो दिए जाने की सिफारिश की थी, उसके बाद आबकारी आयुक्त कार्यालय ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

यह आदेश एक सितंबर से प्रदेश में लागू हो जाएगा। यानी लाइसेंसी शराब दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि शराब बेचने के दौरान खरीददार को कैश मेमो दे। इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रदेश की मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मदिरा क्रेता के पास मदिरा क्रय किए जाने का प्रमाण की सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से प्रदेश के सभी फुटकर विक्रय से संबंधित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया जाता है।

दुकानदारों के लिए इस बिल को ठेका अवधि की समाप्ति तक यानी 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों के लिए यह भी जरूरी होगा कि मदिरा दुकानों पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। जिससे कि दुकानदार द्वारा कैश मेमो नहीं दिए जाने की स्थिति में क्रेता शिकायत भी कर सकेगा। यहां बता दें कि वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग के गृह क्षेत्र मंदसौर में पिछले दिनों जहरीली शराब के सेवन से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसीएस गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने भी मुख्यमंत्री को सौंपे रिपोर्ट में कैश मेमो देने की अनुशंसा की थी।

राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मप्र का रहा सबसे बेहतर प्रदर्शन

भोपाल (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश ने जुलाई माह में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश ने योजना में 147 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। जुलाई माह में प्रदेश के लगभग 22 लाख 57 हजार 791 हितग्राहियों को 10, 916 लाख रुपएका मातृत्व लाभ वितरित किया गया। इस योजना में जुलाई माह में मातृत्व लाभ वितरित करने में भी मध्यप्रदेश अव्वल रहा है।

प्रदेश ने अर्जित की 147 प्रतिशत उपलब्धि

भारत सरकार द्वारा एक जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गई है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। नगद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार लाना भी योजना का उद्देश्य है। योजना में समस्त गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को प्रथम जीवित बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद प्रति हितग्राही पांच हजार रुपए तीन किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त एक हजार रुपए आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन करने पर, द्वितीय किस्त दो हजार रुपए प्रसव पूर्व जांच करने और गर्भावस्था के छह माह पूर्ण होने पर तथा दो हजार रुपए की तीसरी किश्त बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं बच्चे के प्रथम चक्र के टीकाकरण पूर्ण होने पर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में प्रदान करने का प्रावधान है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया देश के शैक्षणिक जगत को नया आयाम

राज्यपाल ने संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया

भोपाल (एजेंसी)। मप्र के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि संगीत विश्वविद्यालय प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा में ललित कलाओं, गीत संगीत को शामिल कराने में स्कूलों का मार्ग दर्शन और सहयोग करें। श्री पटेल राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के 14वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को गुरुवार को यहां राजभवन से आभासी माध्यम द्वारा संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश के शैक्षणिक जगत को नया आयाम दिया है। हमारी मौलिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आवश्यकता नई सोच और नवाचारों के साथ प्रयास की है।

राज्यपाल ने कहा कि मधुर संगीत आत्मा को शांत और एकाग्र करता है। संगीत के स्वर, ध्वनि और भाव ईश्वर अराधना का माध्यम है। भारतीय संगीत का जो रूप है, उसके बीज वैदिक काल में ही पड़ चुके थे। सामवेद उन वैदिक ऋचाओं का संग्रह है, जो गाये जा सकते हैं। प्राचीन काल से ही ईश्वर की अराधना के लिए भजनों के प्रयोग की परम्परा रही है। यहां तक कि यज्ञ आदि के अवसर पर भी समूह गान होते थे।उन्होंने कहा कि संगीत शारीरिक और मानसिक रुप से हमें स्वस्थ बनाये रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने का अभूतपूर्व अवसर दिया है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है। मधुर संगीत आत्मा को शांत और एकाग्र करता है। उन्होंने कहा है कि कलाएं केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, ये संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करती है। संस्कृति से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है।

संगीत परमात्मा की साधना का माध्यम : उषा ठाकुर

पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि संगीत परमात्मा की साधना का माध्यम है। संस्कृति की रीढ़ है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने में विश्वविद्यालय को पहल करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में 64 कलाओं की जानकारी की व्यवस्था की गई है। इन सभी कलाओं के संबंध में संक्षिप्त शैक्षणिक कोर्स शुरु करने के संबंध में आम जन से मांग प्राप्त हो रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में पहल की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए कहा है।

मॉडल विकासखंड की कार्य-योजना कागजों में नहीं मुझे खेतों में दिखाना : कुशवाह

मौका-मुआयना में मिली गड़बड़ी, तो होगी सख्त कार्रवाई

गुरुवार को भोपाल में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने मॉडल विकासखंडों की कार्ययोजना की समीक्षा की।

भोपाल (एजेंसी)। मॉडल विकासखंडों के लिए बनाई गई कार्य-योजनाओं का उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खेत पर जाकर निरीक्षण करूंगा। कार्य-योजना किसानों से मिले सुझावों के आधार पर बनाई है, यह भी देखूंगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने उद्यानिकी मॉडल विकासखंडों के प्रभारी अधिकारियों की विंध्याचल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में यह बातें कहीं।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कार्य-योजना को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखें। कार्य-योजना जमीन पर उतारें। मॉडल विकासखंड बनाने में उच्च अधिकारियों से निर्देश की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत किसानों के सुझावों की है। किसान उद्यानिकी की कौन-सी फसल लेना चाहते हैं, किस प्रकार के बीज चाहते हैं, स्थानीय परिवेश के अनुसार खेती का उनका अनुभव कार्य-योजना में शामिल करें। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी किसानों से सीधा संवाद करें। किसानों से मिले सुझावों को कार्य-योजना के मूल में रखें। मॉडल विकासखण्ड प्रभारी ग्रामों का लगातार दौरा करें। परंपरागत ढंग से योजनाओं के क्रियान्वयन को करने के स्थान पर नवाचारों को अमल में लाएं। इस माह के अंत से मॉडल विकासखंडों का उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा करने की बात श्री कुशवाह ने कही। उन्होंने कहा कि वह खेतों पर पहुंचकर किसानों से बातचीत कर कार्य-योजना के संबंध में जानकारी लेंगे। मॉडल विकासखंड प्रभारी और जिले के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मॉडल विकासखंड कार्य-योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं होना चाहिए। लापरवाही और गड़बड़ली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उद्यानिकी विभाग की केंद्र और राज्य प्रवर्तित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उद्यानिकी आयुक्त एमके अग्रवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलों से आये विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

तालिबान के लिए मुनव्वर राना के समर्पण और स्नेह से स्तब्ध : भूपेंद्र सिंह

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आतंकवादी संगठन तालिबान के लिए शायर मुनव्वर राना का समर्पण और स्नेह देखकर वे स्तब्ध हैं। श्री सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि आतंकवादी संगठन तालिबान के लिए शायर मुनव्वर राना का समर्पण तथा स्नेह देखकर स्तब्ध हूं। अपनी रचनाओं में मां का भावुक चित्रण करने वाले इस शायर ने एक बार फिर अपनी करतूत से भारत मां का अपमान किया है। मानवता तथा देश के विरुद्ध यह उनका घोर आपत्तिजनक आचरण है। परमेश्वर से प्रार्थना है कि मुनव्वर राना को सद्बुद्धि प्रदान करें। उन्हें स्वस्थ मानसिकता के आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से चर्चा में गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

महंगाई के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए केंद्रीय मंत्री खटीक

भोपाल (एजेंसी)। देशभर में तेजी के साथ महंगाई प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री भी महंगाई के मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा लेकर आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने गुरुवार को यहां मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं तक रसोई गैस पहुंचाने को बड़ी उपलब्धि बताया। हालांकि महंगा गैस सिलिंडर भराने के लिए गरीब की जेब खाली होने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दे पाए।

पेट्रोल- डीजल के दामों में वृद्धि से जुड़े सवालों को टालते हुए उठकर चले गए। इससे पहले केंद्रीय विधि विधायी मंत्री एसपीएस बघेल भी महंगाई के मुद्दे पर कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाए थे। केंद्रीय मंत्री की आशीर्वाद यात्रा का ग्वालियर भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वीरेंद्र कुमार खटीक प्रांत कार्यवाह यशंवत इंदापुरकर से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर भी

गए और संघ के प्रक्कलपों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री खटीक ने बताया कि इस सत्र में विपक्ष का व्यवहार काफी गैर जिम्मेदाराना रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी विपक्ष की भूमिका निभाई है। सरकार की नीतियों का विरोध भी गरिमा में रहकर किया है। इस बार विपक्ष ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। यहां तक की सदन की कार्रवाई चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के टेबिल के रजिस्टर उठाकर फेंक दिए। परंपरा के अनुसार दोनों सदनों में नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव नियुक्त मंत्रियों को सीधे क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है।

दीपावली तक घरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की योजना

डॉ. खटीक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उज्जवला योजना से अंतिम छोर के व्यक्ति तक रसोई गैस सिलिंडर पहुंचाने का काम किया। संकट की घड़ी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। फिलहाल दीपावली तक लोगों के घरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की योजना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर देश कदम बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी लड़ाकू विमान सहित अन्य हथियार स्वदेश में निर्मित किए जा रहे हैं। पहले किसी महामारी के फैलने पर टीका हमारे यहां तक पहुंचने में तीन साल से अधिक का समय लग जाता था। कोरोना संक्रमण में हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया और अब तक 50 फीसदी से अधिक लोगों का देश में टीककरण हो चुका है।

केंद्रीय मंत्री खटीक की जनआशीर्वाद यात्रा आज भोपाल पहुंचेगी

भोपाल । केंद्र सरकार के नवनियुक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की जनआशीर्वाद यात्रा 20 अगस्त को भोपाल पहुंचेगी। यात्रा के दौरान श्री खटीक शहर के धर्मगुरुओं, प्रबुद्धजनों, साहित्यकारों से उनके निवास पहुंचकर भेंट करेंगे। यात्रा शाम को भाजपा कार्यालय पहुंचेगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं जनआशीर्वाद यात्रा प्रदेश प्रभारी भगवानदास सबनानी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्रीखटीक ग्वालियर से सुबह 5.00 बजे भोपाल आएंगे। इसके बाद वे वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यहां सुबह 9.30 बजे जिला इकाई द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे सुबह 10.15 बजे पं दीनदयाल की मूर्ति पर लालघाटी में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10.30 बजे संत हिरदाराम की कुटिया पहुंचकर दर्शन करेंगे। 11 बजे शासकीय विद्यालय नयापुरा लालघाटी में टीकाकरण केंद्र का भ्रमण करेंगे। सुबह 11.15 बजे गुफा मंदिर एवं 11.30 बजे गुरुनानक टेकरी पर गुरुद्वारा दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रभुनगर कमेटी हाल नानक टेकरी पर अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। 1.30 बजे जिला कार्यालय पहुंचेंगे। 1.45 बजे मां कर्फ्यू वाली माता के दर्शन करेंगे। दोपहर 2.00 बजे लोकतंत्र सेनानी पं ओम मेहता के निवास पर भोजन करेंगे। दोपहर 3.00 बजे काली घाट पर मां काली दर्शन के पश्चात पं अटलबिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शौर्य स्मारक पर चक्र समर्पण करेंगे। बोर्ड आफिस चौराहा पर अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम 4.15 बजे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ देवेंद्र दीपक से भेंट करेंगे। शाम 4.40 बजे शहीद देवाशीष शर्मा के निवास बी. सेक्टर शाहपुरा पहुंचकर परिजनों से भेंट करेंगे। वीरेंद्र कुमार खटीक शाम 4.40 बजे मनीषा मार्केट, 1100 क्वार्टर, बांसखेडी, अरेरा पेट्रोल पंप, विद्युत नगर, आरबीआई कालोनी, सुभाष स्कूल चौराहा होते हुए शाम 5.45 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। शाम 7.00 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिला भोपाल द्वारा स्वागत किया जाएगा। रात्रि 8.00 बजे श्री खटीक मंडल अध्यक्ष मुकुल लोखंडे के निवास पर भोजन करेंगे।

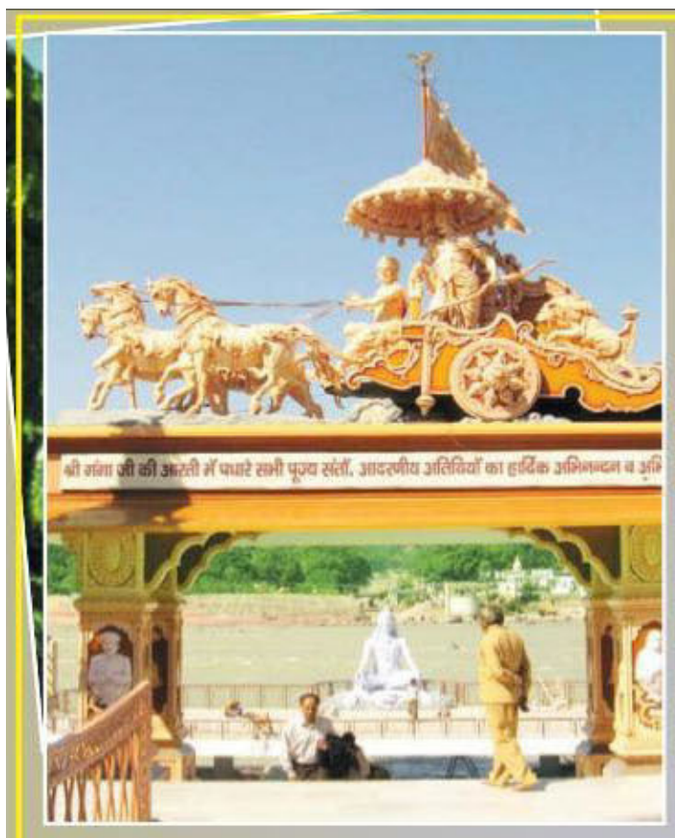

हिमालय का प्रवेशद्वार

ऋषिकेश

ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहां के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है।

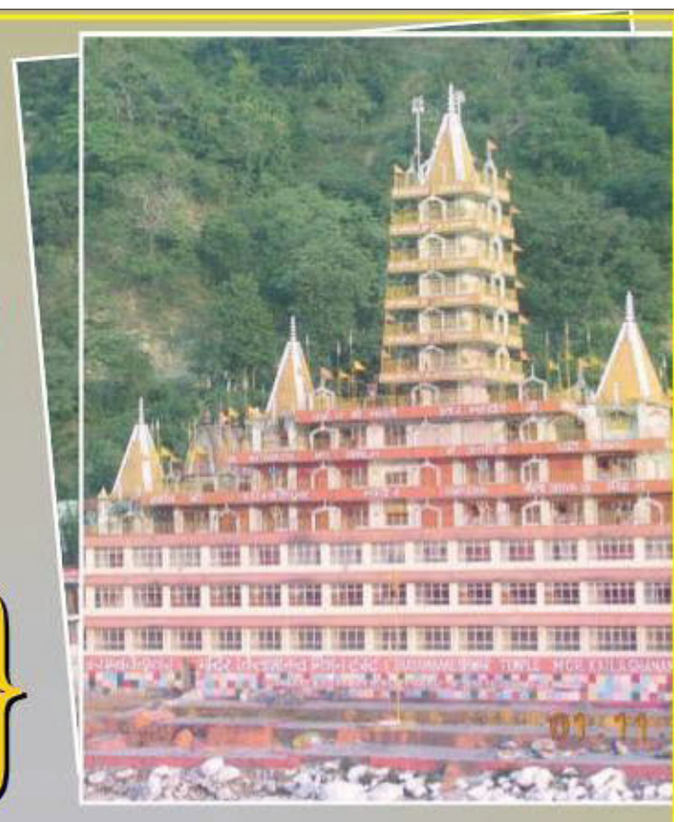

हिमालय का प्रवेश द्वार, ऋषिकेश जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। हरिद्वार से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश विश्व प्रसिद्ध एक योग केंद्र है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखण्ड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुन्दरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेशद्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहां के आश्रमों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शान्ति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं।

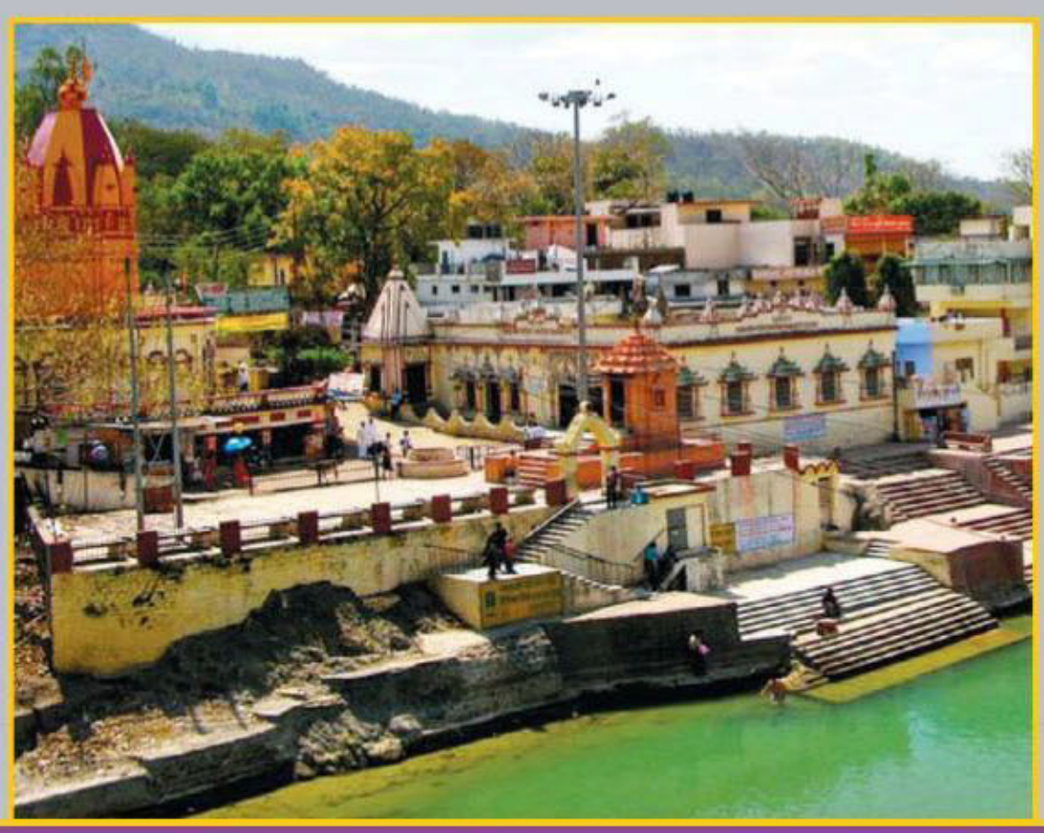

प्रचलित कथाएं

ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहां के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। 1939 ई. में लक्ष्मण झूले का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि राभ्या ने यहां ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के अवतार में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है।

लक्ष्मण झूला

गंगा नदी के एक किनार को दूसरे किनारे से जोड़ता यह झूला शहर की खास पहचान है। इसे 1939 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर हैं। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला के समान राम झूला भी नजदीक ही स्थित है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है। इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है।

त्रिवेणी घाट

ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है जहां प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिन्दु धर्म की तीन प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दायीं ओर मुड़ जाती है। शाम को होने वाली यहां की आरती का नजारा बेहद आकर्षक होता है।

राम झूला पुल

स्वामी विशुद्धानन्द द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। स्वामी जी को काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता था। इस स्थान पर बहुत से सुन्दर मंदिर बने हुए हैं। यहां खाने पीने के अनेक रेस्तरां हैं जहां सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। आश्रम की आसपास हस्तशिल्प के सामान की बहुत सी दुकानें हैं।

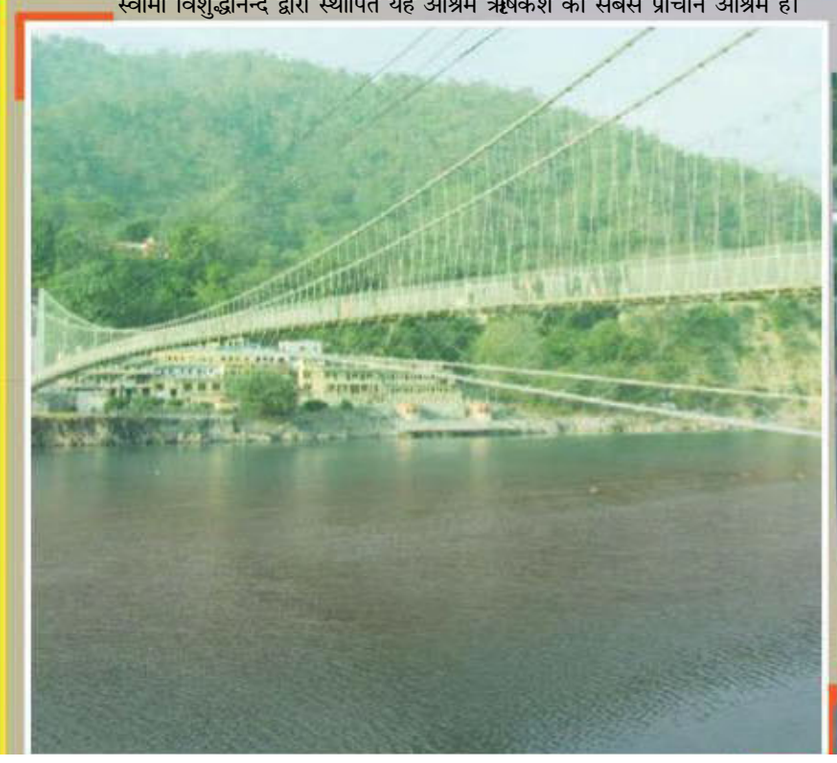

नीलकंठ महादेव मंदिर-

लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव के से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं।

भरत मंदिर-

यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसे 12 शताब्दी में आदि गुरू शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल रूप 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उस हमले के बाद आज तक संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालीग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। आदि गुरू शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्रीयंत्र भी यहां देखा जा सकता है।

कैलाश निकेतन मंदिर-

लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। 12 खंड़ों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं।

वशिष्ठ गुफा-

ऋषिकेश से 22 किमी. की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर बहुत से साधु विश्राम और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। कहा जाता है यह स्थान भगवान राम और बहुत से राजाओं के पुरोहित वशिष्ठ का निवास स्थल था। वशिष्ठ गुफा में साधुओं को ध्यानमग्न मुद्रा में देखा जा सकता है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है।

गीता भवन-

राम झूला पार करते ही गीता भवन है जिसे 1950 ई. में श्रीजयदयाल गोयन्काजी ने बनवाया गया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहां रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षण बनाती हैं। यहां एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी और गीताप्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है। प्रवचन और कीर्तन मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहां भक्ति संगीत की आनंद लिया जा सकता है।

कैसे जाएं

वायुमार्ग–

ऋषिकेश से 18 किमी. की दूरी पर देहरादून के निकट जौली ग्रान्ट एयरपोर्ट नजदीकी एयरपोर्ट है। इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइटें इस एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ती है।

रेलमार्ग–

ऋषिकेश का नजदीकी रलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो शहर से 5 किमी. दूर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है।

सड़क मार्ग

दिल्ली के कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डीलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से दिल्ली और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती हैं।

तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहां सैकड़ों कमरे हैं।

खरीददारी

ऋषिकेश में हस्तशिल्प का सामान अनेक छोटी दुकानों से खरीदा जा सकता है। यहां अनेक दुकानें हैं जहां से साड़ियों, बेड कवर, हैन्डलूम फेबरिक, कॉटन फेबरिक आदि की खरीददारी की जा सकती है। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैन्डलूम शॉप, खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं जहां से उच्चकोटि का सामान खरीदा जा सकता है।

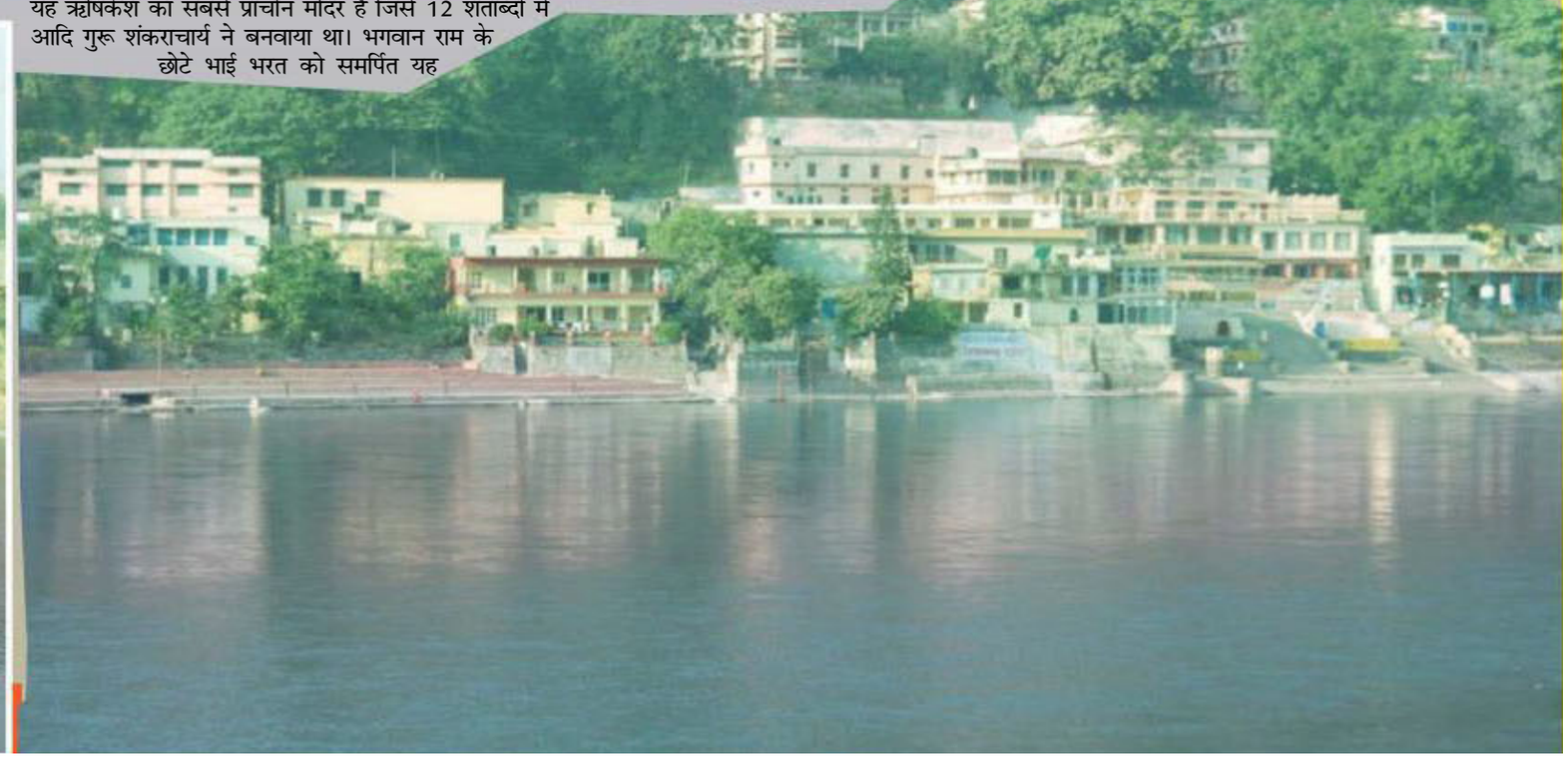

स्मिथ व वॉर्नर की टीम में वापसी

टी 20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, फिंच संभालेंगे कमान

सिडनी (एजेंसी)। एरॉन आरोन फिंच इस साल ओमान और यूएई में होने वाले टी 20 विश्व कप में एक मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए चुनी गई टीम में सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ की वापसी हुई है। स्मिथ जहां अभी-अभी कोहनी की चोट से उबरे हैं जबकि कप्तान फिंच ने हाल ही में घुटने की सर्जरी कराई थी। अब वह पूरी तरह ठीक हैं। वार्नर को वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के हालिया दौरों के लिए आराम दिया गया था। ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, मार्कस स्टोइनिस और पैट कमिंस भी कुछ समय तक टीम से बाहर रहने के बाद एक्शन में वापस आ गए हैं।

चयनकर्ता ने विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी और गेंदबाज झाए रिचर्डसन और एंड्रयू टाय सहित नौ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। ये सभी वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में खेले थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता द्वारा घोषित 15 सदस्यीय टीम में अनकैप्ड जोश इंगलिस भी शामिल हैं। क्रिकेटर से चयनकर्ता बने जॉर्ज बेले ने कहा, हमें विश्वास है कि यह टीम एक बेहद प्रतिस्पर्धी है और आने वाले टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, जो अपनी-अपनी भूमिकाओं में सामूहिक अनुभव के साथ मिलकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीमों के खिलाफ सफलता हासिल कर सकते हैं। टी20 विश्व कप का आयोजन इस साल भारत में होना था लेकिन भारत में कोरोना महामारी की खराब स्थिति को देखते हुए आईसीसी ने विश्व कप को यूएई और ओमान की संयुक्त मेजबानी में कराने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया 23 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 12 चरण के मुकाबले के साथ अपने टी-20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

एरॉन फिंच कप्तान, एश्टन एगर, पैट कमिंस उपकप्तान, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस विकेटकीपर, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्वेपसन, मैथ्यू वेड विकेटकीपर, डेविड वार्नर, एडम जम्पा। रिजर्व खिलाड़ी : डैनियल क्रिश्चियन, नाथन एलिस, डैनियल सैम्स।

ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप जीतने में सक्षमः पोंटिंग

पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस साल यूएई और ओमान में होने वाले टी 20 विश्व कप को जीतने में सक्षम है। अनकैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को सीनियर खिलाड़ी मैथ्यू वेड के बैकअप के तौर पर 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है। पोंटिंग इस बात से खुश हैं कि टी 20 विश्व कप के लिए इंग्लिस को ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह दी गई है। पोंटिंग ने ट्वीट कर कहा, इंग्लिस को अवसर मिलते देखना सुखद है। वह मजे के लिए स्कोर करते हैं और अगर उन्हें लिया गया है तो यह बेहतरीन है। ओवरऑल यह अच्छी टीम है और मेरे ख्याल से टी20 विश्व कप जीतने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम गत विजेता वेस्टइंडीज, 2010 की चैंपियन इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और पहले राउंड से क्वालीफाई करने वाली दो अन्य टीमों के साथ ग्रुप -1 में है।

स्टीव स्मिथ ने नेट्स पर शुरू की प्रैक्टिस

ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेले का मानना है कि स्टार बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ इस साल के अंत में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए समय पर फिट हो जाएंगे। स्मिथ जिन्हें साल के शुरुआत में आईपीएल के दौरान बाएं कोहनी में चोट आई थी अब उन्होंने न्यू साउथ वेल्स में नेट्स में अभ्यास करना शुरू कर दिया है। बेली ने कहा, उनकी तैयारी सही चल रही है, मेरे पास जो अपडेट है उसमे मुझे पता चला है कि वह हर सेशन के दौरान 100 से ज्यादा गेंदे खेल रहें है। बेली ने आगे कहा, एक ऐसा समय आता है जहां आपको जोखिम लेना होता है। हमें स्मिथ पर पूरा भरोसा है, वह अपने शरीर को बखूबी जानते हैं और उन्हें पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे र्दशन किया जाता है।

सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट

ओसाका, बार्टी और केरबेर तीसरे दौर में

सिनसिनाटी । दूसरी वरियता प्राप्त जपान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका के कोको गॉफ को 4-6, 6-3, 6-4 से हरा कर यहां चल रहे सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में जगह बना ली है।

इस बीच, महिला में वर्ल्ड नंबर वन ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी भी ग्रेट ब्रिटेन की हीथर वॉटसन के खिलाफ 6-4, 7-6 की जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गई। जबकि गत चैंपियन बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने एलिसन रिस्के को 6-2, 7-5 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की अरिना सबलेंका को स्पेन की पाउला बाडोसा के हाथों राउंड-32 के मुकाबले में 5-7, 6-2, 7-6 से हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी की पूर्व विश्व नंबर वन एंजेलिक केरबेर ने राउंड ऑफ 16 में एलिना स्वितोलिना को 7-5, 2-6 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

सानिया मिर्जा बाहर

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अपनी ट्यूनीशियाई जोड़ीदार ओन्स जबूर के साथ यहां सीधे सेटों में हार के बाद एटीपी मास्टर्स 1000 वेस्टर्न और साउदर्न सिनसिनाटी ओपन की महिला युगल स्पर्धा से बाहर हो गईं। उन्हें टूर्नामेंट के पहले दौर के मैच में रूस की वेरोनिका कुडरमेतोवा और कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना की जोड़ी से 5-7, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। एक घंटे तीन मिनट तक चले इस मैच में सानिया और जबूर ने चार एस मारे और दो डबल फाल्ट किए।

पेरिस ओलंपिक के लिए तीन साल का समय कम

तुरंत करनी होगी वापसीः बिंद्रा

मुंबई। ओलंपिक में व्यक्ति इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट शूटर अभिनव बिंद्रा का मानना है कि पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए तीन साल का समय होना कठिन होगा।

बिंद्रा ने कहा, टोक्यो में ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा और सात पदक आए। यहां बेहतरीन पल और कुछ भावुक करने वाले पल देखने को मिले। लेकिन खेल इसी का नाम है। मैं अगले ओलंपिक साईकल को थोड़ा कठिन मान रहा हूं क्योंकि इसके लिए समय कम है। आमतौर पर एथलीट ओलंपिक के एक साल बाद तक थोड़ा रिलेक्स रहते हैं जिससे उन्हें आराम मिलता है और वह रिकवर होते हैं। लेकिन इस बार उन्हें तुरंत ही वापसी करनी होगी। पेरिस के लिए कम समय रहना टोक्यो 2020 का कोरोन वायरस के कारण एक साल के लिए स्थगित होना रहा है। आमतौर पर ओलंपिक चार साल में होते हैं लेकिन इस बार इसके लिए तीन वर्ष का समय शेष रह गया है। बिंद्रा ने कहा, हम लोग टॉप लीडरशीप के बारे में बात करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमें दूसरे स्तर के लीडरशीप में और क्वालिटी लाने की जरूरत है।

भारत तीन अक्टूबर से शुरू करेगा सैफ में अभियान

कोलकाता । भारतीय फुटबॉल टीम मालदीव के माले स्थित नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में तीन अक्टूबर से शुरू हो रही सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार है। भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम फिलहाल कोलकाता में प्रशिक्षण शिविर में है, जहां वह आगामी टूर्नामेंट के लिए मुख्य कोच इगोर स्टिमैक की कोचिंग में तैयारी कर रही है। भारत को सैफ चैंपियनशिप से पहले सितंबर के पहले हफ्ते में नेपाल के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलने हैं। इसके बाद भारत तीन अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से अपने 2021 सैफ चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत करेगा।

सैफ चैंपियनशिप शेड्यूल

तीन अक्टूबर : भारत-बांग्लादेश
छह अक्टूबर : भारत-श्रीलंका
आठ अक्टूबर : भारत-नेपाल
11 अक्टूबर : भारत-मालदीव
13 अक्टूबर : फाइनल।

टेस्ट के प्रति कोहली का जूनून अद्भुत

पीटरसन ने की तारीफ

मुंबई (एजेंसी)। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्डस के मैदान पर खेले दूसरे टेस्ट में जहां भारत ने मेजबान टीम को 151 रनों से हराया था, उस मैच में आक्रामक रवैये के कारण भारतीय कप्तान विराट कोहली को कुछ आलोचना से गुजरना पड़ा था। हालांकि, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारतीय कप्तान की सरहना करते हुए कहा कि उनका जोश और जूनून अद्भुत है और वह जिस तरह से अपने टीम को टेस्ट क्रिकेट में प्रेरित करते हैं, वह अविश्वसनीय है।

पीटरसन ने कहा, विराट को टेस्ट क्रिकेट का महत्व पता है और एक शानदार खिलाड़ी के रूप में वह वैसा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पीटरसन ने अपने ब्लॉग में लिखा, कोहली जानते हैं कि खेल के दिग्गज माने जाने के लिए उन्हें इस प्रारूप के साथ-साथ टी20 में भी अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसलिए वह इस प्रारूप को इतना महत्व देते हैं और ऐसे समय में जब टेस्ट क्रिकेट को जितना प्यार मिल रहा है, तो इस सुपरस्टार का खेल के प्रति जुनून देख कर अच्छा लग रहा है। पीटरसन ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पहले टेस्ट में बारिश ने खलल नहीं डाला होता तो मेहमान टीम सीरीज में 2-0 से बढ़त बना चुकी होती।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मुशफिकुर और लिटन की बांग्लादेश टीम में वापसी

ढाका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 19 सदस्यीय टीम घोषित की है जिसमें मुशफिकुर रहीम और लिटन दास को भी जगह दी गई है। बांग्लादेश के मुख्य चयनकर्ता मिनहाजुल अबेदिन ने कहा, जब आप अपने दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को वापस टीम में देखते हैं तो यह राहत देता है। मुझे यकीन है कि विश्व कप से पहले यह उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट है और इसे देखते हुए वे इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मुशफिकुर जिम्बाब्वे दौरे से बीच में लौटे थे जिसके कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफसीरीज में शामिल होने के लिए 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहने की जरूरत थी। हालांकि, वह ऐसा नहीं कर सके थे और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर होना पड़ा था।

बांग्लादेश की टीम इस प्रकार है : महमुदुल्लाह कप्तान, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, सौम्य सरकार, लिटन दास, मुसादेक हुसैन साइकत, अफीफ नईम शेख, नुरुल हसन सोहान, शमीम हुसैन, रुबेल हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शैफ उदिन,, शोरिफुल इस्लाम, तैजुल इस्लाम, शाक मेहदी हसन, अमिनुल इस्लाम बिपलोब और नासुम अहमद।

आईपीएल खेलने से विश्वकप में फायदा मिलेगाः मुस्ताफिजुर

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान का मानना है कि यूएई में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन यूएई में ही होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई सीरीज में अपनी विविधताओं का चतुराई से उपयोग करते हुए कापफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। वह अपने इस प्रदर्शन को न्यूजीलैंड के साथ-साथ शेष आईपीएल में भी उसी तरह जारी रखना चाहते हैं। मुस्ताफिजुर ने कहा कि वह अपने मौजूदा फॉर्म से खुश हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं। मैं अच्छी लय में हूं और न्यूजीलैंड तथा आईपीएल में अच्छा खेलने से आईसीसी टी 20 विश्व कप के लिहाज से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा।

रोहन 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में

वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप

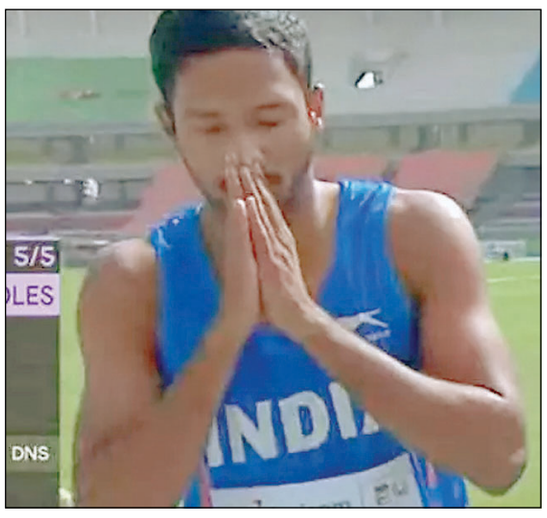

नैरोबी । भारत के रोहन कांबले ने यहां चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में गुरूवार को पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

भारतीय 4 गुना 400 मीटर मिश्रित रिले टीम के कांस्य पदक जीतने के एक दिन बाद भारतीय खेमे में मुस्कराहट बिखरने वाले वह एक मात्र भारतीय थे। रोहन ने पांच हीट में से आखिरी हीट में चौथे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनायी। उन्होंने 55.00 सेकंड का समय निकाला। इससे पहले भारत के अनु कुमार पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गए थे। अनु कुमार ने 1:50.26 का समय लिया और अपनी शुरूआती हीट में चौथे स्थान पर रहे। पूजा महिलाओं की 800 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पायीं और अब वह शुक्रवार को होने वाली 1500 मीटर स्पर्धा में उतरने की तैयारी करेंगी। पुरुष शॉट पुट के फाइनल में जगह बनाने वाले अमनदीप सिंह धालीवाल फाइनल में पहले दो प्रयास फाउल कर गए और तीसरे प्रयास में 17.08 मीटर की थ्रो के साथ 12वें स्थान पर रहे।

यूपी बैडमिंटन संघ ने किया सिंधु को सम्मानित

लखनऊ । टोक्यो ओलम्पिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु को गुरूवार को उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ ने सम्मानित किया। बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित एक समारोह में संघ के चेयरमैन विराज सागर दास एवं अध्यक्ष डा. नवनीत सहगल ने सिंधु को सम्मानित किया।सम्मान समारोह में मौजूद सिंधु के पिता पीवी रमन्ना और माता पी. विजया भी उपस्थित रहे। बैडमिंटन के प्रति समर्पण को याद करते हुए सिंधु के पिता को डा. नवनीत सहगल एवं माता पी. विजया को विराज सागर दास ने सम्मानित किया। सम्मान के बाद पीवी सिंधु ने बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी के उभरते हुए शटलरों से मुलाकात की और उनको कड़ी मेहनत के साथ खूब खेलने की सीख दी। उन्होंने कहा, समर्पण के साथ लगन से प्रैक्टिस के साथ ही आगे बढ़िए। इससे आने वाले समय में आप भी अपने देश के लिए पदक जीतकर नाम रोशन कर सकते है। गौरतलब है कि पीवी सिंधु लगातार दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी और भारत की दूसरी एथलीट बन गयी है। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक-2016 में रजत पदक जीता था जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक-2020 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।

पाक दौरे को लेकर सुरक्षा की समीक्षा करेगा इंग्लैंड

नई दिल्ली । इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी पड़ोसी देश अफगानिस्तान में संघर्ष को लेकर चिंताओं के बीच इस साल सर्दियों में प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे से पहले सुरक्षा की समीक्षा करेगा। इंग्लैंड 16 साल में पहली बार अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाला है, जिसमें पुरुष टीम रावलपिंडी में दो टी20 और महिला टीम दो टी20 और तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी। हालांकि, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पड़ोसी देश पाकिस्तान में नए सुरक्षा मुद्दों पर चिंता बढ़ गई है। ईसीबी के प्रवक्ता के हवाले से कहा, किसी भी दौरे के लिए सुरक्षा प्रक्रियाएं और जांच चल रही है। हम इस शरद ऋतु में पाकिस्तान के पुरुषों और महिलाओं के दौरे की योजना बना रहे हैं।

खिलाड़ियों ने दिलाया एक स्वर्ण व दो रजत

भोपाल। हैदराबाद के हुसैन सागर में 12 से 19 अगस्त तक आयोजित 35वीं हैदराबाद सेलिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और दो रजत पदक मध्यप्रदेश को दिलाया। चैंपियनशिप के लेजर 4.7 इवेंट में अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी रितिका दांगी ने स्वर्ण और नेहा ठाकुर ने रजत पदक मध्यप्रदेश को दिलाया। चैंपियनशिप के लेजर रेडियल इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी राम मिलन यादव ने मध्यप्रदेश को रजत पदक दिलाया। प्रतियोगिता में रितिका दांगी और नेहा ठाकुर ने एशियन गेम्स के पहले राउंड का ट्रायल जीत लिया।एशियन गेम्स में भारतीय टीम का चयन करने के लिए तीन राउंड सिलेक्शन ट्रायल खेले जाएंगे। पदक विजेता खिलाड़ियों को नौसेना प्रमुख एवं यार्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडमिरल कर्मवीर सिंह द्वारा मैडल प्रदान कर पुरुस्कृत किया गया। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने हैदराबाद सेलिंग चैंपियनशिप में एशियन गेम्स के पहले राउंड का ट्रायल जीतने और मध्यप्रदेश को स्वर्ण और रजत पदक दिलाने वाली खिलाड़ी क्रमशः रितिका दांगी और नेहा ठाकुर के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने रजत पदक विजेता खिलाड़ी राममिलन यादव को भी बधाई दी है।खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक पवन जैन ने ओलंपिक के महीने में मध्यप्रदेश सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न इवेंट्स में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए तीनों पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी चोटिल, भारत को टेस्ट सीरीज में मात देना लगभग नामुमकिन!

नई दिल्ली. इंग्लैंड दौरे पर रन बनाना और जीत हासिल करना किसी टीम के लिए आसान नहीं होता लेकिन जिस तरह टीम इंडिया ने अंग्रेजों को लॉर्ड्स में 151 रनों से हराया है उसे देखकर ये लग रहा है कि ये सीरीज विराट एंड कंपनी की झोली में जाने वाली है. मौजूदा टेस्ट सीरीज के दो मुकाबलों में इंग्लैंड के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों नाकाम साबित हुए हैं. शायद ही कभी इंग्लैंड को अपनी धरती पर इतना बेबस देखा गया हो. वैसे इस बेबसी की एक बड़ी वजह उसके खिलाड़ियों का चोटिल होना भी है. इंग्लैंड के 1-2 नहीं बल्कि 6-6 बड़े खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं और इसका सीधा-सीधा असर उसके प्रदर्शन पर पड़ रहा है. आइए आपको बताते हैं इंग्लैंड के कौन से बड़े खिलाड़ी भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं और वो किस चोट से जूझ रहे हैं.

इंग्लैंड को जोफा आर्चर की कमी सबसे ज्यादा खल रही है. दाएं हाथ का ये तेज गेंदबाज रफ्तार के साथ-साथ गजब की लाइन लेंग्थ पर गेंदबाजी करता है. 13 टेस्ट में 42 विकेट चटकाने वाले आर्चर कोहनी की चोट से जूझ रहे हैं. आर्चर की चोट इतनी गंभीर है कि वो पूरे सालभर तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे.

दाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज क्रिस वोक्स भी चोट की वजह से पहले दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं और तीसरे टेस्ट की टीम में भी उनका नाम नहीं है. वोक्स ऐड़ी की चोट से जूझ रहे हैं. वोक्स ने 38 टेस्ट में 112 विकेट लिये हैं और साथ ही ये खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करता है. एक टेस्ट शतक के दम पर वोक्स ने 1321 रन बनाए हैं. साफ है इंग्लैंड की टीम को इस ऑलराउंडर की कमी जरूर खल रही होगी. जोफा आर्चर के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड के पास एक और बेहद तेज गेंदबाज मौजूद था. नाम है ऑली स्टोन. लेकिन ये खिलाड़ी भी कमर की चोट से परेशान है. यही वजह है कि टेस्ट टीम में ये भी शामिल नहीं है. ऑली स्टोन ने 3 टेस्ट में 10 विकेट लिये हैं और ये खिलाड़ी 150 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार तक गेंद फेंकता है.

बेन स्टोक्स को शारीरिक चोट तो नहीं लगी है लेकिन इंग्लैंड का ये दिग्गज ऑलराउंडर मानसिक तौर पर अनफिट है. स्टोक्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था. उन्होंने खुद को मानसिक रूप से थका हुआ बताया. स्टोक्स गेंद और बल्ले से पूरा खेल पलट देते हैं और पिछले 2-3 सालों में उन्होंने इंग्लैंड को कई टेस्ट मैच जिताए हैं. स्टोक्स की कमी इंग्लैंड को काफी ज्यादा खल रही है. लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद अचानक स्टोक्स की वापसी की बातें उठने लगी थीं.

भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड भी चोटिल हो चुके हैं. 524 टेस्ट विकेट लेना वाले ये गेंदबाज लॉर्ड्स टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गया था. ब्रॉड की पिंडली में चोट लगी जिसके बाद वो पूरी टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गए. ब्रॉड के बाहर होने के बाद इंग्लैंड लॉर्ड्स में 151 रनों से हार गया.

करोड़ों में बिक रहे मेसी के आंसू

जिस टिशू पेपर से आंखें पोछी थी उसकी नीलामी

नई दिल्ली। लियोनेल मेसी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में होती है। अब उनकी आंसू की एक-एक बूंद भी बेशकीमती हो चली है,, तभी तो उस टिशू पेपर की कीमत करोड़ों में पहुंच गई जिसे मेसी ने इस्तेमाल किया था। टिशू बेचने वासे शख्स का दावा है कि मेसी का जेनेटिक भी इस टिशू में शामिल ह, जिससे लोगों को फुटबॉल खिलाड़ी का क्लोन बनाने में मदद मिलेगी। मेसी ने जब से होश संभाला वह स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का हिस्सा थे। 34 साल के इस अर्जेंटीना फुटबॉलर ने जीवन के 21 साल बार्सिलोना में गुजारने के बाद बीते दिनों उसे अलविदा कह दिया। यह लम्हा उनके लिए बेहद भावुक था। मीडिया से बात करते हुए वह रो पड़े। आंखों से आंसू छलकने लगे। इस दौरान उनकी पार्टनर एंटोनेला वहीं थीं। नम आंखों को पोछने के लिए उन्होंने मेसी को एक टिशू पेपर दिया था,, जो अब तकरीबन 7.43 करोड रुपए में बिक रहा है।

ऑनलाइन मिल रहा टिशू

दरअसल, एक अज्ञात व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने मेसी द्वारा इस्तेमाल किए गए टिशू को इकट्ठा कर लिया है और इन टिशू के लिए महंगे दर पर बिक्री के लिए एक ऑनलाइन विज्ञापन भी दिया है। अर्जेंटीना के मीडिया आउटलेट मिशनेस ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार एक लोकप्रिय वेबसाइट मरकाडो लिब्रेश पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। एक ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपनी ने मेसी के उस टिशू को बारीकी से प्लास्टिक के पैकेट में बंद किया गया था, साथ ही भावुक मेसी की तस्वीर भी लगाई है।

पेरिस में घर की तलाश में मेसी

मेसी इन दिनों पेरिस में घर तलाश रहे हैं। लियोनल मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब से लगभग 35 मिलियन यूरो लगभग तीन अरब रुपए का करार किया है,, जो नेमार37 मिलियन यूरो यानि लगभग तीन अरब 22 करोड़ रुपए से कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी, उनकी पत्नी और तीन बच्चे पेरिस के जिस ले रॉयल मोनसेउ होटल में ठहरे हैं वहां एक रात की कीमत 20 हजार यूरो यानी 17.5 लाख रुपए है।

बिपाशा को मिला रजत, संजू और भतेरी फाइनल में

नई दिल्ली । भारत की बिपाशा को 76 किग्रा वर्ग के फाइनल में गुरूवार को हारकर रूस के उफा में चल रही जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक से संतोष करना पड़ा जबकि दो अन्य भारतीय महिला पहलवानों संजू देवी ने 62 किग्रा और भतेरी ने 65 किग्रा के फाइनल में जगह बना ली। संजू और भतेरी अब शुक्रवार को फाइनल में रूसी और मोल्दोवा पहलवानों के खिलाफ उतरेंगी। इस बीच सीतो ने 55 किग्रा वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की की पहलवान को 11-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया जबकि आरजू 68 किग्रा वर्ग में चोटिल होने के कारण कांस्य पदक मुकाबले में नहीं उतरीं। स्नेह कल 72 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। ग्रीको रोमन वर्ग के मुकाबले शुक्रवार से शुरू होंगे और कल पांच वर्गों के मकाबले खेले जाएंगे।